नवम्बर, 2021 वर्ष : 42 अंक : 11

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

१७वें कशाग के तीन नई क्लोन सिक्यांग पेंपा छेरिंग के साथ।

मूल्य :10 रु , वार्षिक : 100 रु

नवम्बर, 2021 वर्ष : 42 अंक :11

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित

तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्राओं के विरोध में चेक गणराज्य के नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी , जिगमे सुलट्रिम

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन पलजोर , तेनजिन जोरदेन

वितरण प्रबंधक
जामयंग छोपेल, छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

करुणा और अहिंसा 1

दलाई लामा : चीन के नेता 'संस्कृतियों की विविधता को नहीं समझते' 2

१६वें कशाग के तीन कलोनों को मुख्य न्यायाधीश आयुक्त ने शपथ दिलाई 3

जिनेवा में सिक्योंग ने गणमान्य व्यक्तियों, छात्रों और तिब्बत समर्थकों से मुलाकात की 4

तिब्बत के पर्यावरण और मानवाधिकारों का मुद्दा नैतिकता का है, राजनीति का नहीं: बर्न में सिक्योंग 5

स्थायी रणनीति समिति की पहली बैठक 6

खाम ड्रैकगो में तिब्बती बौद्ध स्कूल को जबरन तोड़ा गया 7

तिब्बत के सोंगोन प्रांत में लगभग ८० तिब्बती भिक्षुओं को मठों से बाहर निकाला गया 8

त्सोल्हो प्रांत में तिब्बती पार्टी के सदस्यों को घर में धार्मिक अनुष्ठान करने पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए 9

नौकरी दिए जाने के वादों के बावजूद तिब्बती विश्वविद्यालय के स्नातकों को काम नहीं मिल रहा है हान मूल के चीनियों से प्रतिस्पर्धा और मंदारिन भाषा में दक्षता की अनिवार्यता तिब्बतियों के लिए नौकरियों को दुर्लभ बनाती है। 10

'फ्री तिब्बत: ए वायस फ्रॉम असम' ने गुवाहाटी में तिब्बती कार्यकर्ता के अभियान की मेजबानी की 11

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया ने दिल्ली में अपने राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सह-संयोजकों और क्षेत्रीय संयोजकों की बैठक बुलाई 12

समाचार -

यूपी में बुद्ध पीजी कॉलेज द्वारा 'तिब्बत के लिए एक दिन' कार्यक्रम आयोजित किया गया 13

समर्पित तिब्बत समर्थक स्वर्गीय मोहन सिंह के आवासीय एवं निर्वाचन क्षेत्र जिला देवरिया में एक दिन 14

उत्तर प्रदेश के पडरौना में उदित नारायण पीजी कॉलेज ने 'ए डे फॉर तिब्बत' का आयोजन किया 15

भारत-तिब्बत समन्वय संघ ने 'तिब्बत और तिब्बती: वर्तमान और भविष्य' शीर्षक से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया 16

तिब्बत पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, तिल का ताड़ बना सकता है चीन 17

निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी की पुस्तक का विमोचन किया और तिब्बत पर वार्ता में भाग लिया 18

'कॉप-२६ टीम तिब्बत' वैश्विक जलवायु प्रणाली में तिब्बत की भूमिका को उजागर करने के लिए ग्लास्गो में 19

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष रूप से चिंता वाले देशों की सूची में चीन को शामिल किया 20

लिथुआनिया ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने का आह्वान किया 21

चीनी राष्ट्रपति की २०१६ यात्रा के दौरान चेक सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया: चेक अदालत का फैसला 22

मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com

तिब्बती शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने गतिरोध से बहुत पहले एलएसी पर काम शुरू किया था 23

अपनी बात

निर्वासित तिब्बत सरकार के साथ वार्ता पुनः प्रारंभ करे चीन

भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से संचालित निर्वासित तिब्बत सरकार, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से तिब्बती जनता द्वारा चुनी गई है, सम्पूर्ण विश्व के लिये अनुकरणीय उदहारण है। वर्तमान तिब्बती संसद निर्वाचन की दृष्टि से १७ वीं संसद है। इसी प्रकार कसाग अर्थात् तिब्बती मंत्रिमंडल १६ वीं कसाग है। तिब्बती संविधान के अनुरूप तिब्बती संसद ने अक्टूबर माह में अपने सत्र के दौरान मंत्रिमण्डल में शामिल करने हेतु तीन महिलाओं के नाम स्वीकृत किये थे। उन्हीं तीन महिलाओं को तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयुक्त द्वारा नवंबर में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में शामिल ये तीन सदस्य हैं - गैरी डोल्मा, थारलाम डोल्मा और नोर्ज़िन डोल्मा। केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन में विभिन्न पदों पर रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण दायित्व सफलतापूर्वक निभाने का अनुभव इन्हें प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान तिब्बती प्रधानमंत्री पेंपा त्सेरिंग के कुशल नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल अपनी समस्त जिम्मेदारियाँ सफलतापूर्वक निभायेगा, ऐसी आशा करना उचित है। समस्त तिब्बती एवं समर्थक आशान्वित हैं कि पेंपा त्सेरिंग के मागदर्शन में तिब्बत सरकार तिब्बत समस्या के समाधान हेतु सभी उपयुक्त प्रयास करेगी।

चीन के पूर्व प्रधानमंत्री देंग श्याओ पिंग ने तिब्बती धर्मगुरु परमपावन दलाई लामा, जो कि तिब्बत के राजप्रमुख भी थे, को स्पष्ट बता दिया था कि तिब्बत को आजाद नहीं किया जायेगा। इसी आधार पर दलाईलामा ने १९७० में "मध्यममार्ग" का प्रस्ताव रखा। इसे "वास्तविक स्वायत्तता" कहा जाता है। इस प्रस्ताव को तिब्बती संसद की सर्वसम्मत स्वीकृति मिली हुई है। यह प्रस्ताव चीन के संविधान तथा राष्ट्रीयता संबंधी कानून के अनुकूल है। इसके अनुसार चीन सरकार अपने पास प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक मामले रख ले और कृषि, शिक्षा समेत अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तिब्बत सरकार को मिले। इस व्यवस्था से चीन की क्षेत्रीय एकता-अखंडता तथा संप्रभुता पूर्ववत् सुरक्षित रहेगी और तिब्बतियों को भी स्वशासन का अधिकार मिल जायेगा। वर्तमान समय में चीन सरकार ने तिब्बत के कई क्षेत्र अपने भौगोलिक क्षेत्र में मिला लिये हैं। "वास्तविक स्वायत्तता" अर्थात् "मध्यममार्ग की नीति" संपूर्ण तिब्बत में क्रियान्वित हो।

चीन सरकार साजिशपूर्वक तिब्बत का चीनीकरण कर रही है। तिब्बत के मठ, मंदिर, आध्यात्मिक संस्थान तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल बर्बाद किये जा रहे हैं। वहाँ चीनी मूल के लोग बड़ी संख्या में बसाये जा रहे हैं। तिब्बत में ऊँचे पदों पर सिर्फ चीनी हैं। कृषि एवं उद्योग में तिब्बती सिर्फ मजदूर बना दिये गये हैं। तिब्बती महिलाओं की जबरन नसबंदी भी चीनीकरण की इसी साजिश का हिस्सा है। ऐसी चिंताजनक स्थिति में तिब्बती एवं तिब्बत समर्थकों की प्राथमिकता तिब्बती पहचान की सुरक्षा है। "विश्व के तीसरे ध्रुव" तथा "संसार की छत" से विख्यात तिब्बत के ग्लेसियर नष्ट होते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों की लूट और चीनी भोगवाद के शिकार तिब्बती पर्यावरण के प्रति संपूर्ण विश्व चिंतित है। संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थायें तिब्बत में चीन द्वारा जारी अमानवीय नीति तथा मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध हैं।

चीन के साथ वर्ष २०१० के बाद तिब्बती प्रतिनिधिमंडल की वार्ता रुकी पड़ी है। ऐसा साम्राज्यवादी चीन की हठधर्मिता से हुआ है। विश्व जनमत वार्ता पुनः होने के पक्ष में है, क्योंकि तिब्बत समस्या के समाधान से विश्वशांति मजबूत होगी। अभी तिब्बती संघर्ष शांतिपूर्ण एवं अहिंसक है। दलाई लामा की प्रेरणा एवं आशीर्वाद का यह परिणाम है। वे स्वयं को तिब्बती राजप्रमुख के दायित्व से मुक्त कर चुके हैं। वे अपने समस्त राजनीतिक अधिकार तिब्बत सरकार को सौंप चुके हैं। वे सिर्फ आध्यात्मिक जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। उनके मतानुसार २१वीं शताब्दी के लिये शांति-अहिंसा का मंत्र ही ठीक है।

शांति के लिये नोबल पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने तिब्बत के प्रश्न को अन्तरराष्ट्रीय प्रश्न बना दिया है। पड़ोसी होने के कारण भारत के लिये यह और गंभीर प्रश्न है। दलाई लामा के अनुसार भारत से ही बौद्ध दर्शन तिब्बत पहुँचा था। तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक-आध्यात्मिक संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच मधुर और विश्वसनीय संबंध थे। स्वतंत्र तिब्बत में भारतीय अपनी सुविधानुसार कैलाश-मानसरोवर के और तिब्बती बेरोकटोक भारत में बौद्ध स्थलों के दर्शन कर लेते थे। इसी कारण दलाई लामा ने अपने हजारों अनुयायियों सहित शरण के लिये भारत को चुना। आज भारतीय समाज में तिब्बती अपने व्यवहार से सबका दिल जीत चुके हैं। अभी चीन पर दबाव बढ़ाने का उपयुक्त अवसर है। चीन में फरवरी २०२२ में आयोजित हो रहे शीतकालीन ओलंपिक के कूटनीतिक बहिष्कार में शामिल देशों की संख्या और बढ़ने वाली है। इस आयोजन के माध्यम से चीन सरकार तिब्बत की गंभीर स्थिति पर पर्दा डाल रही है। लेकिन उसे मालूम होना चाहिये कि वह इस मुद्दे पर १९५९ से ही बेनकाब है। तिब्बत में तथाकथित विकास के उसके दुष्प्रचार से कोई भी प्रभावित नहीं होने वाला है। चीन सरकार को चाहिये कि वह यथाशीघ्र तिब्बत सरकार एवं दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता पुनः प्रारंभ करे। वह तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करे अन्यथा उसे तिब्बत को पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (राजस्थान)
मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

• करुणा और प्रेम

dalailama.com, १७ नवंबर, २०२१

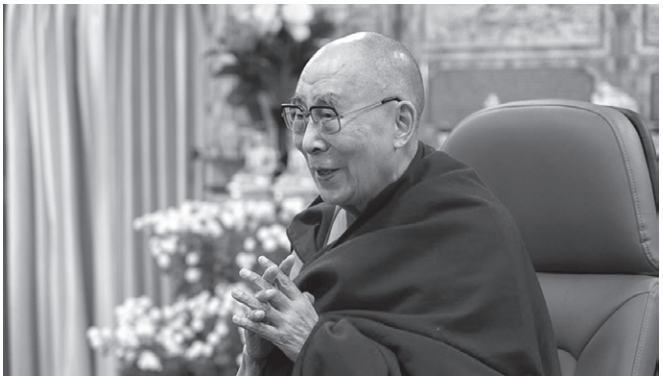

करुणा और प्रेम पर आयोजित वेबिनार मे जुड़े परम पवन दलाई लामा।

थेकचेन छोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। परम पावन दलाई लामा आज १७ नवंबर की प्रातः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनका स्वागत संस्थान के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल ने किया। उन्होंने परम पावन को आपदा प्रबंधन के संदर्भ में करुणा और प्रेम के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया।

परम पावन ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, 'सबसे पहले मैं भारतीय तरीके से नमस्ते कहना चाहता हूं और इसके बाद ताशी देलेक कहना चाहूंगा, जैसा कि हम तिब्बती में कहते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'भारत और तिब्बत के बीच काफी अद्भुत विशेष संबंध हैं। सातवीं शताब्दी में तिब्बती सम्राट के चीनी शाही परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध थे। तिब्बती सम्राट ने एक चीनी राजकुमारी से शादी की और हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने चीनी खान-पान और अन्य चीजों का आनंद लिया होगा। फिर भी जब यह विचार आया कि तिब्बती में लेखन का क्या स्वरूप होगा, तो उन्होंने चीनी परंपरा के प्रति अनिच्छा जताई और इसके बजाय भारतीय देवनागरी लिपि पर आधारित तिब्बती वर्णमाला को डिजाइन करने का विकल्प चुना।'

'परंपरागत रूप से हम भारत को न केवल पवित्र भूमि के रूप में देखते हैं, बल्कि अपने ज्ञान के स्रोत के रूप में भी देखते हैं। बुद्ध भारत के ही थे, जिन्होंने भारत में अपने ज्ञान का प्रचार किया। पाली भाषा भी यहां की एक परंपरा है, जिसका अनुकरण मुख्य रूप से श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में किया जाता है। इसी तरह संस्कृत यहां की दूसरी परंपरा है। आठवीं शताब्दी में तिब्बती सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय के लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वान शांतरक्षित को तिब्बत में आमंत्रित किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तिब्बतियों की अपनी लिखित भाषा है, उन्होंने उन्हें भारतीय बौद्ध साहित्य का तिब्बती में अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप कांग्यूर और तेंग्यूर की रचना हो गई। कांग्यूर में १०० खंडों में बुद्ध वचनों का संकलन है जबकि तेंग्यूर में बुद्ध के बाद के आचार्यों की रचनाएं हैं जो २०० से अधिक खंडों में है। इनमें नागार्जुन और असंग जैसे ज्यादातर भारतीय आचार्य शामिल हैं।'

'संस्कृत परंपरा के अनुयायियों ने बुद्ध की इस सलाह को स्वीकार किया कि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया उसे केवल इसलिए स्वीकार न करें कि ये बुद्ध के वचन हैं, बल्कि उन पर सवाल उठाएं और उनकी जांच करें। धर्मकीर्ति का 'वैध अनुभूति का संग्रह' और चंद्रकीर्ति का 'मध्यम मार्ग में प्रवेश' नालंदा परंपरा के प्रमुख ग्रंथ थे, जिनमें उन्होंने तर्क और मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला था। मैं चंद्रकीर्ति के 'मध्यम मार्ग में प्रवेश' ग्रंथ के साथ ही उनकी टिप्पणी को अपनी मेज पर रखता हूं और उन्हें हर दिन पढ़ता हूं।'

'बचपन में मैं अनिच्छुक छात्र था, लेकिन मैंने दिन-प्रतिदिन इन ग्रंथों के कुछ हिस्सों को याद किया और जो मैंने अपने शिक्षक से सीखा उसे दोहराया।'

'चूंकि हमारा प्रशिक्षण तर्कों और कारणों पर आधारित है, इसलिए हम वैज्ञानिकों के साथ उपयोगी बातचीत करने में सक्षम हुए हैं। हमने जिन विषयों पर चर्चा की है उनमें मन की कार्यप्रणाली और नकारात्मक भावनाओं को कैसे बदला जाए, जैसे विषय शामिल हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं बौद्ध दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने में सक्षम हूं। मैं अपने मित्र फ्रांसिस्को वरेला की तरह सोचना पसंद करता हूं, जो बौद्ध धर्म में भी गहरी रुचि रखने वाले वैज्ञानिक थे। वह कहते थे, 'मैं अपनी बौद्ध टोपी पहन रहा हूं, या अब, मैं अपनी वैज्ञानिक टोपी पहन रहा हूं। क्योंकि वह इसी दृष्टिकोण के अनुयायी रहे थे। आधुनिक शिक्षा को प्राचीन भारतीय ज्ञान के साथ जोड़ने का समय आ गया है, जिसके आधार पर हम इस ग्रह पर ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

'आपदा प्रबंधन के संबंध में हमारे कार्य सकारात्मक हैं या नहीं, यह हमारी प्रेरणा पर निर्भर करता है। मुख्य कारक यह है कि क्या हमारे पास करुणामय रवैया है। भारत में 'अहिंसा' और 'करुणा' की पुरानी परंपराएं हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उन्हें आधुनिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जा सकता है।

अतीत में, महात्मा गांधी ने यह दिखाया कि अहिंसा को व्यावहारिक रूप में कैसे लागू किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और बिशप टूटू और संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जैसी हस्तियों ने उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की और उनका अनुकरण किया। किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने और अहिंसा का दर्शन न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि यह व्यावहारिक रूप से भी उपयुक्त हैं।'

परम पावन ने बताया कि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में बिताया है और उनका मस्तिष्क भारतीय ज्ञान से भरा है। उसने घोषणा की कि वह एक शरणार्थी हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने उन्हें एक घर दिया, पहले मसूरी में और बाद में धर्मशाला में। उन्होंने टिप्पणी की कि जब वे पहली बार मसूरी से धर्मशाला गए तो उन्हें लगा कि वे कहीं दूर जा रहे हैं और एक अच्छी तरह से जुड़े हुए स्थान को छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ आए राजनीतिक अधिकारी पं. पंत ने भविष्यवाणी की कि धर्मशाला वह स्थान है जहां से दलाई लामा का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचेगा।

उन्होंने कहा, 'उस समय मैंने सोचा था कि वह अतिशयोक्ति कर रहे थे, लेकिन वह सही हो सकते थे। वैसे भी, मैं प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में जो समझता हूं उसे साझा करने में मुझे खुशी हो रही है जो लोगों को मन की शांति खोजने में मदद करके एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान दे सकता है। चूंकि हर कोई शांति से रहना चाहता है, इसलिए हमें यह समझना होगा कि लड़ाई-झगड़े, हत्या और हथियारों पर भारी मात्रा में धन खर्च करना पुरानी बात हो चुकी है। हमें तर्क और शिक्षा के आधार पर दुनिया को बदलना है।'

श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर में परम पावन ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि धार्मिक साधना चित्त की शांति प्राप्त करने का एक साधन है और चूंकि सभी धार्मिक परंपराएं अपने मूल में करुणा की शिक्षा देती हैं, इसलिए वे सभी सम्मान के योग्य हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि सभी प्राणी सुखी रहना चाहते हैं और सभी को सुखी और दुख से मुक्त होने का अधिकार है। करुणा का असर लोकतंत्र पर भी पड़ता है।

जहां तक मनुष्य का संबंध प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से है, इस बारे में परम पावन ने

सलाह दी कि हमें हमेशा एक व्यापक तथा समग्र दृष्टिकोण से चीजों को देखने की आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रौद्योगिकी मानवता की सेवा के लिए है और हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए।

अस्वीकार्य अन्याय और अपमान का सामना करने की बात कहने वाले एक वैज्ञानिक चाहते थे कि हानिकारक व्यवहार का जवाब करुणा से कैसे दिया जाए। परम पावन ने उन्हें बताया कि खुश रहने के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं करनेवाली 'अहिंसा' आवश्यक है, और सभी के साथ करुणा से व्यवहार करने का नाम 'करुणा' है। उन्होंने यह मानने के महत्व का उल्लेख किया कि धार्मिक साधना का मूल विभाजनकारी राजनीतिक नीति की तरह नहीं है। इसका सार करुणा है, जिसके प्रकाश में दूसरों के साथ भेदभाव या संघर्ष की कोई बात नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर, उन्होंने कहा कि भारत सभी धर्मों का एक साथ शांतिपूर्वक रहने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

यह टिप्पणी करते हुए कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली मन की शांति विकसित करने के तरीकों पर बहुत कम ध्यान देती है, परम पावन ने 'अहिंसा' और 'करुणा' को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया।

उन्होंने कहा, 'जब हम बच्चे होते हैं तो हम सभी अपनी मां के स्नेह में पलते होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं प्यार और स्नेह हमें कम प्रासंगिक लगने लगते हैं। हालांकि, करुणा का अभ्यास यहां और अभी एक शांतिपूर्ण व्यक्ति होने के बारे में है। करुणा का एक पहलू यह आत्मसात करना है कि अन्य लोग हमारे जैसे ही हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी एक-दूसरे की मदद करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। फिर भी, मैं वास्तव में उन लोगों और संगठनों की प्रशंसा करता हूं जो आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं।

'कोविड-१९ महामारी उन लोगों की मदद करने के लिए भी कई अवसर लेकर आई है जो बीमार पड़ गए हैं या अपने खोए हुए रिश्तेदारों के दुख से घिरे हैं। दूसरों को कठिनाइयों में देखना मनोबल महसूस करने का कारण नहीं है, इससे हमारी करुणा की भावना को मजबूत करना चाहिए।'

परम पावन ने टिप्पणी की कि पूर्व में वैज्ञानिकों ने आंतरिक शांति की भूमिका पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यह बदल गया है और शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए मन की शांति प्राप्त करने का महत्व बहुत बेहतर समझा जा रहा है। क्रोध और भय जैसी विनाशकारी भावनाओं के विघटनकारी प्रभाव और उसके चिंता को जन्म देने की प्रवृत्ति की भी अधिक स्पष्ट रुप से पहचान की जाती है। इसी तरह, इस बात की मान्यता बढ़ती जा रही है कि करुणा धैर्य और समस्याओं के प्रति अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण लाती है। परम पावन ने यह जांचने के लिए कि क्या कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, शांतिदेव की सलाह का हवाला दिया। अगर कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है तो उसे करना चाहिए; यदि उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है तो उनके बारे में चिंता करने से स्थिति में सुधार नहीं होगा।

परम पावन ने याद करते हुए बताया, 'मैंने अपना देश, अपनी स्वतंत्रता खो दी और इतना विनाश देखा और फिर भी मुझे अभी भी लगता है कि मेरा मध्यम मार्ग दृष्टिकोण वास्तविक स्वायत्तता की तलाश में जो हमें हमारी संस्कृति को संरक्षित करने की अनुमति देता है, एक यथार्थवादी विकल्प है। इतना ही नहीं, इसी का प्रभाव है कि बड़ी संख्या में चीनी भाई-बहन बौद्ध धर्म में रुचि ले रहे हैं और हमारी परंपराओं से सीख सकते हैं।'

मेजर जनरल बिंदल ने बातचीत का सारांश प्रस्तुत किया और चार बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए परम पावन को धन्यवाद दिया। ये चार बिंदु हैं- सभी धार्मिक परंपराओं का सार 'करुणा' और 'अहिंसा' है; शिक्षा हमें करुणा विकसित करने और मन की शांति प्राप्त करने का साधन प्रदान करती है; हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने के तरीकों को देखने की जरूरत है और अंत में हमें मानवता की एकता के बारे में जागरुक होने की जरूरत है।

प्रो संतोष कुमार ने परम पावन को प्रेम और करुणा, सहानुभूति और आनंद पर विस्तार से बताने और न केवल आपदा प्रबंधन में, बल्कि सामान्य मानवीय संबंधों में भी करुणा की आवश्यक भूमिका की पुष्टि करने के लिए धन्यवाद दिया।

परम पावन ने उत्तर दिया, 'मैं बहुत खुश हूं कि मुझे करुणा और अहिंसा के बारे में आपसे बात करने का अवसर मिला, जो आपकी अपनी प्राचीन भारतीय परंपरा के प्रमुख तत्व हैं। दुनिया को बड़े पैमाने पर इन गुणों के बारे में पता होना चाहिए। इन विचारों को धर्मनिरपेक्ष आधार पर अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करने से हमें अत्यधिक लाभ होगा। आपको धन्यवाद।'

• दलाई लामा : चीन के नेता 'संस्कृतियों की विविधता को नहीं समझते'

reuters.com, १० नवंबर २०२१

एंटोनी स्लोदकोव्स्की और ऐलेन लिज़

टोक्यो, १० नवंबर (रायटर)। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बुधवार को चीन के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे 'संस्कृतियों की विविधता' को नहीं समझते हैं और चीन की मुख्य हान नस्ल वाले समूह का देश पर बहुत अधिक नियंत्रण है।

लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके मन में इंसानों के तौर पर 'चीनी भाइयों और बहनों' के खिलाफ कुछ भी नहीं है और उन्होंने व्यापक रुप से कम्युनिस्ट और मार्क्सवाद के विचारों का समर्थन किया है।

86 वर्षीय दलाई लामा टोक्यो में आयोजित एक ऑनलाइन समाचार सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इसमें वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पश्चिमी चीन में स्थित झिंझियांग में अल्पसंख्यकों के दमन पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने भारत में अपने आवास से कहा, 'मैं माओत्से तुंग के समय से कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को जानता हूं। उनके विचार अच्छे हैं। लेकिन कभी-कभी वे बहुत चरम, कड़े नियंत्रण करते हैं।' उन्होंने सोचा कि नई पीढ़ी के नेताओं के तहत चीन में चीजें बदल जाएंगी।

'तिब्बत और झिंझियांग के बारे में भी हमारी अपनी अनूठी संस्कृति है। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट नेता इतने संकीर्ण हैं कि, वे संस्कृतियों की विविधता को नहीं समझ सकते हैं।'

उन्होंने इस बात पर गौर किया कि चीन में न केवल नस्लीय हान लोग रहते हैं, बल्कि अलग-अलग समुदाय के अन्य लोग भी हैं। उन्होंने कहा कि 'वास्तव में, देश पर हान लोगों द्वारा बहुत अधिक नियंत्रण है।'

चीन ने १९५० में अपने सैनिकों के इस क्षेत्र में भेजकर चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिसे वह 'शांतिपूर्ण मुक्ति' कहता है। तब से तिब्बत चीन के सबसे प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बन गया है।
चीनी शासन के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद १९५९ में भारत भाग आए दलाई

लामा को बीजिंग एक ख़तरनाक 'अलगाववादी' मानता है। उन्होंने अपनी दूरस्थ पहाड़ी मातृभूमि में भाषाई और सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए वैश्विक समर्थन प्राप्त करने के लिए दशकों तक काम किया है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को एक नियमित प्रेस वार्ता में दलाई लामा के साथ संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उन्हें 'एक अलग अलगाववादी राजनीतिक समूह' कहा।

काफी नाजुक

दलाई लामा ने कहा कि उन्होंने व्यापक रूप से कम्युनिज्म और मार्क्सवाद के विचारों का समर्थन किया। हंसते हुए उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने एक बार कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के बारे में सोचा था लेकिन एक दोस्त ने उन्हें मना कर दिया था।

इन दिनों इस क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के प्रमुख केंद्र ताइवान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यह द्वीप चीन की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं का सच्चा भंडार है, क्योंकि मुख्य भूमि का अब 'बहुत अधिक राजनीतिकरण' हो गया है।

उन्होंने कहा, 'आर्थिक रूप से ताइवान को मुख्य भूमि चीन से बहुत मदद मिलती है और मुझे लगता है कि संस्कृति, बौद्ध धर्म सहित चीनी संस्कृति के बारे में मुख्य भूमि के चीनी भाई-बहन ताइवान के भाइयों और बहनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।'

हालांकि दलाई लामा ने कहा कि उनकी चीन के नेता शी जिनपिंग से मिलने की कोई योजना नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा कि 'मैं बूढ़ा हो रहा हूं' इसलिए पुराने दोस्तों मिलने के लिए फिर से यात्रा करना चाहता हूं- लेकिन ताइवान से बचना चाहूंगा क्योंकि इसके और चीन के बीच संबंध 'काफी नाजुक हैं'।

हाल के वर्षों में मुसलमानों की शिकायतों के बावजूद उन्होंने धार्मिक सद्भाव के केंद्र के रूप में भारत की प्रशंसा करते हुए कहा, 'मैं यहां भारत में शांति से रहना पसंद करता हूं।'

हालांकि, अंत में उन्होंने कहा कि विश्वास है कि सभी धर्मों का एक ही संदेश है।

'सभी धर्म प्रेम का संदेश ही देते हैं और विचारों के तौर पर अलग दर्शन का उपयोग करते हैं। तो अब समस्या (है) राजनेताओं में है। कुछ मामलों में कुछ अर्थशास्त्री धर्म के इस अंतर का उपयोग करते हैं। तो अब, धर्म का भी राजनीतिकरण किया जाता है - इसलिए वह समस्या है।

ऐलेन लाइज़ और एंटोनी स्लोदकोव्स्की द्वारा रिपोर्टिंग; क्रिश्चियन श्मोलिंगर और रॉबर्ट बिरसेला द्वारा संपादन

• १६वें कशाग के तीन कलोनों को मुख्य न्यायाधीश आयुक्त ने शपथ दिलाई

tibet.net, १० नवंबर, २०२१

धर्मशाला। सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग द्वारा नामित और १वीं निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा अनुमोदित १६वें कशाग के तीन कलोनों को आज सुबह गंगचेन किइशोंग के सिक्योंग सभागार में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक रूप से शपथ दिलाई गई।

शपथ ग्रहण समारोह में सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग, 17वीं तिब्बती संसद के सदस्य, न्याय आयुक्त, स्वायत्त निकायों के प्रमुख और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभिन्न विभागों के सचिव शामिल थे।

तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयोग के मुख्य न्यायाधीश आयुक्त सोनम नोरबू डागपो ने नए कलोनों को पद की शपथ दिलाई। इनमें कलोन डोल्मा ग्यारी, कलोन थर्लम डोल्मा और कलोन नोरज़िन डोल्मा ने शपथ ली है।

• जिनेवा में सिक्योंग ने गणमान्य व्यक्तियों, छात्रों और तिब्बत समर्थकों से मुलाकात की

tibet.net, ०४ नवंबर, २०२१

सिक्यांग पेंपा छेरिंग और संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी मिशन के चार्ज डी'अफ़ेयर्स बेंजामिन डब्ल्यू मोएलिंग।

जिनेवा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने ०३ नवंबर को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी मिशन में चार्ज डी'अफ़ेयर्स बेंजामिन डब्ल्यू मोएलिंग और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी मुलाकात की।

सिक्योंग ने डॉ. माइकल वैन वॉल्ट वैन प्राग के साथ ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जिनेवा (आईएचआईडी) में लगभग २० छात्रों के एक समूह से भी बात की। दोनों ने '२१वीं सदी में कूटनीति: तिब्बत की राजनीतिक और कानूनी स्थिति की जांच' विषय पर बात की। इंटरेक्शन का आयोजन स्टूडेंट इनिशिएटिव ऑन एशिया (एसआईए) द्वारा किया गया था।

बातचीत के दौरान डॉ. वैन प्राग ने समझाया कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है और चीनी सरकार के इस दावे का कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं है। सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र के विकास के बारे में बात की और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की संरचना और कार्यों पर एक संक्षिप्त परिचय दिया। वार्ता के बाद प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया।

दोपहर में सिक्योंग ने स्विस-तिब्बती मैत्री संघ के फ्रांसीसी-भाषी सदस्यों से मुलाकात की। बैठक के दौरान सिक्योंग ने भविष्य की योजनाओं और गतिविधियों पर चर्चा की और समूह के सवालों का जवाब दिया।

• तिब्बत के पर्यावरण और मानवाधिकारों का मुद्दा नैतिकता का है, राजनीति का नहीं: बर्न में सिक्योंग

tibet.net

सिक्यांग पेंपा छेरिंग और स्विस सांसद के साथ।

०५ नवंबर। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ०४ नवंबर को जिनेवा से बर्न पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद सिक्योंग स्विट्जरलैंड नेशनल काउंसिल (स्विस संसद) गए, जहां उन्होंने स्विस नेशनल काउंसिल के सदस्य निकोलस वाल्डर और तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समर्थक समूह के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों सुश्री प्रिस्का बिरर-हेमो और सेड्रिक वर्मुथ से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, सिक्योंग ने स्विस नेशनल काउंसिल के सदस्यों को तिब्बत के अंदर चीन द्वारा अपनाई जा रही क्रूर नीतियों और तिब्बती धर्म, संस्कृति, भाषा और पहचान पर इसके विनाशकारी प्रभावों से अवगत कराया। तिब्बत के मुद्दे को उठाने के लिए स्विस सांसदों से आग्रह करते हुए, सिक्योंग ने कहा कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है और तिब्बत के पर्यावरण और मानवाधिकारों का मुद्दा नैतिकता का मामला है, राजनीति का नहीं। सिक्योंग ने आगे तिब्बती आंदोलन और तिब्बती लोगों के न्यायोचित कारणों को बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं और गतिविधियों पर चर्चा की।

निकोलस वाल्डर ने सिक्योंग को तिब्बत के लिए स्विस संसदीय सहायता समूह और इसके वर्तमान २० सदस्यों की संख्या के बारे में सूचित किया। उन्होंने सिक्योंग से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि उन्हें आशा है कि तिब्बत के लिए संसदीय सहायता समूह भविष्य में और सदस्यों के साथ बड़ा होगा।

सिक्योंग और स्विस सांसदों के बीच बैठक का आयोजन स्विस-तिब्बती मैत्री संघ द्वारा किया गया था। स्विस-तिब्बती मैत्री संघ की स्थापना १९८३ में स्विस जनता को तिब्बत के भीतर गंभीर राजनीतिक और मानवाधिकार की स्थिति के बारे में सूचित करने और चीनी सरकार के प्रचार का मुकाबला करने के लिए की गई थी।

बैठक में स्विस-तिब्बती मैत्री संघ के अध्यक्ष थॉमस बुचली, स्विस-तिब्बती मैत्री संघ के उपाध्यक्ष ल्हावांग नोरखांगसर, स्विट्जरलैंड के तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष कर्मा चोएकी और लिचेंस्टीन, क्षेत्रीय के अध्यक्ष त्सेरिंग यूडॉन ने भी भाग लिया। क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ (आरटीडब्ल्यूए) और यूरोप के तिब्बती युवा संघ के उपाध्यक्ष दलहा वांगडेन।

दोपहर में, सिक्योंग ने स्विट्ज़रलैंड स्थित तिब्बती संघों द्वारा आयोजित 'तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं था, एक चीन नीति को छोड़ दिया जाना चाहिए' विषय पर चर्चा में भाग लिया। सिक्योंग के साथ चर्चा में डॉ. माइकल वैन वॉल्ट वैन प्राग, तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समूह के सदस्य रेगुला रयट्ज़, लेखक रॉल्फ बाचली और भारतीय पत्रकार विजय क्रांति शामिल थे। चर्चा का संचालन क्लूडिया सेडिओली मारित्ज़ ने किया।

बैठक में स्विस-तिब्बती मैत्री संघ के अध्यक्ष थॉमस बुचली, स्विस-तिब्बती मैत्री संघ के उपाध्यक्ष ल्हावांग नोरखांग्सर, स्विस-तिब्बती मैत्री संघ के स्विट्जरलैंड और लिचेंस्टीन के तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष कर्मा चोएक्यी और क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ के अध्यक्ष त्सेरिंग यूडॉन और यूरोप के तिब्बती युवा संघ के उपाध्यक्ष दल्हा वांगडेन ने भी भाग लिया।

दोपहर में सिक्योंग ने स्विट्ज़रलैंड स्थित तिब्बती एसोसिएशनों द्वारा आयोजित 'तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं था, एक चीन नीति को छोड़ दिया जाना चाहिए' विषय पर चर्चा में भाग लिया। सिक्योंग के साथ चर्चा में डॉ. माइकल वैन वॉल्ट वैन प्राग, तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समूह के सदस्य रेगुला रयट्ज़, लेखक रॉल्फ बाचली और भारतीय पत्रकार विजय क्रांति शामिल थे। चर्चा का संचालन क्लूडिया सेडिओली मारित्ज़ ने किया।

• स्थायी रणनीति समिति की पहली बैठक

tibet.net, १६ नवंबर, २०२१

धर्मशाला। चीन-तिब्बत वार्ता पर पिछले टास्क फोर्स के 16वें कशाग के विघटन के बाद इसके स्थान पर एक नई स्थायी रणनीति समिति की स्थापना की गई है।

बैठक का मुख्य एजेंडा नई समिति के कार्यक्रमों और उद्देश्यों पर विचार-विमर्श करना है। बैठक में सलाहकार कसूर टेंपा त्सेरिंग, कसूर डोंगचुंग न्गोडुप और पूर्व विशेष दूत केल्सांग ग्यालत्सेन सहित समिति के सभी सदस्य शामिल हैं। सुरक्षा विभाग, सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर), तिब्बत नीति संस्थान (टीपीआई) के सचिव और कशाग सचिवालय के राजनीतिक सचिव भी बैठक में उपस्थित रहे। गदेन फोडरंग कार्यालय के सचिव न्गावा त्सेग्यम ने भी विशेष निमंत्रण पर बैठक में भाग लिया।

हालांकि, पहले स्थायी रणनीति समिति की आंतरिक बैठक हुई थी, लेकिन समिति की यह पहली बैठक है जिसमें सभी सदस्य और सलाहकार उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग ने की।

• खाम ड्रैकगो में तिब्बती बौद्ध स्कूल को जबरन तोड़ा गया

tibet.net, ११ नवंबर, २०२१

तिब्बती बौद्ध स्कूल को ध्वस्त करते चीनी सर्कार के कर्मचारी।

धर्मशाला। तिब्बत के पारंपरिक खाम प्रांत के ड्रैकगो (चीनी: लुहुओ) काउंटी में चीनी अधिकारियों ने झूठा आरोप लगाते हुए कि स्कूल ने भूमि उपयोग कानून का 'उल्लंघन' किया है, तिब्बतियों को आदेश दिया कि एक तिब्बती बौद्ध स्कूल को ध्वस्त कर दिया जाए।

तिब्बत टाइम्स के अनुसार, ड्रैकगो के गदेन रबटेन नामग्यालिंग मठ के प्रशासन द्वारा संचालित गेदेन नांगटेन स्कूल को आधिकारिक आदेश प्राप्त होने के बाद स्वयंसेवी स्थानीय तिब्बतियों की मदद से ३१ अक्तूबर २०२१ को ध्वस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट में स्रोत ने कहा, 'चीनी अधिकारियों ने स्कूल प्रशासन को आदेश दिया था कि वे अगले तीन दिनों में स्वेच्छा से स्कूल को ध्वस्त कर दें अन्यथा सरकार विनाश को अंजाम देने के लिए एजेंसियों को भेजेगी।' अधिकारियों ने आगे स्कूल के फर्नीचर और संपत्तियों को भी जब्त करने की धमकी दी।

स्कूल के विध्वंस के बाद दैनिक जीवनयापन के लिए स्कूल पर निर्भर तिब्बती बच्चे, विशेष रूप से गरीब परिवार की पृष्ठभूमि वाले बच्चे बेदखल कर दिए गए और उन्हें अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर किया गया।

एक तिब्बती स्रोत के अनुसार, स्कूल का विध्वंस बिना सिर पैर के आरोपों पर किया गया, क्योंकि स्कूल पर भूमि उपयोग कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जबकि यह कानून केवल स्थानीय आवासीय भवनों पर लागू होता है।

इसके अलावा अतीत में चीनी अधिकारियों ने लगभग २० छात्रों को स्कूल से यह आरोप लगाते हुए जबरदस्ती निष्कासित कर दिया गया था कि छात्र स्कूलों में जाने की उम्र के नहीं हुए हैं और इस तरह उन्हें उनके घरों में वापस भेज दिया गया।

गेदेन बौद्ध स्कूल ड्रैकगो में स्थित है, जिसे अब सिचुआन प्रांत में शामिल किया गया है। इसका निर्माण २०१४ में गदेन रबटेन नामग्याल लिंग मठ के विद्वानों और भिक्षुओं द्वारा किया गया था। बंद होने से पहले यहां लगभग १३० छात्रों को पारंपरिक और आधुनिक, जैसे कि तिब्बती, चीनी और अंग्रेजी और बौद्ध दर्शन पाठ्यक्रम सहित भाषा और व्याकरण की शिक्षाएं प्रदान की जाती थीं।

अतीत में विशेष रूप से २००८ और २०१२ में, ड्रैकगो काउंटी में तिब्बतियों द्वारा दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियों और इस क्षेत्र में लागू किए गए फरमानों के खिलाफ विभिन्न शांतिपूर्ण विरोधों को देखा गया है। शांतिपूर्ण विरोधों को अक्सर क्रूर दमन और कार्रवाई के साथ निपटाया जाता था। तब से, चीनी अधिकारियों ने स्थानीय तिब्बती की रोजाना की गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर निगरानी और निरीक्षण को और तेज कर दिया है।

इस तरह की घटना तिब्बती संस्कृति और भाषा को बदनाम करने के लिए चीनी सरकार के अभियान में हालिया बढोतरी को दर्शाती है, क्योंकि तिब्बती स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। मनगढ़ंत आरोपों के तहत तिब्बती स्कूलों को जबरन बंद किया जाना आम बात है।

तिब्बती स्कूलों को जबरन बंद करके न केवल तिब्बती बच्चों को उनकी अपनी भाषा और संस्कृति सीखने के अधिकार से वंचित किया गया है, बल्कि उन्हें चीनी सरकारी स्कूलों में जाने के लिए मजबूर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक आत्मसात और भाषा का उत्पीड़न चल रहा है।

• तिब्बत के सोंगोन प्रांत में लगभग ८० तिब्बती भिक्षुओं को मठों से बाहर निकाला गया

tibet.net, ११ नवंबर, २०२१

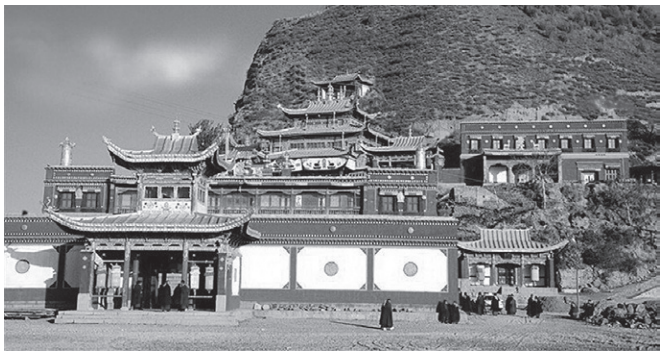

धर्मशाला। तिब्बत टाइम्स के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के सोंगोन प्रान्त (चीनी: किंघई प्रांत) में दो मठों से लगभग ८० तिब्बती भिक्षुओं को जबरन निष्कासित कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, २१ और २२ अक्तूबर २०२१ को, किंघई प्रांत के बायन काउंटी (चीनी: हुआलोंग) में जकयुंग मठ के ३० भिक्षुओं और डित्सा मठ के ५० भिक्षुओं को पुलिस छापे के बाद निष्कासित कर दिया गया और उनके घरों में वापस भेज दिया गया।

अधिकारियों ने मठों पर उस कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत १८ वर्ष से कम उम्र के किसी भी नाबालिग को भिक्षु बनने के लिए मठों में दाखिला लेने से रोकता है। उनका कहना हैकि इन नाबालिगों को स्कूलों में भेजा जाना चाहिए।

चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर निष्कासित भिक्षुओं को निर्देश दिया है कि वे भविष्य में फिर से भिक्षुओं के वस्त्र पहनने स्कूल जाने से बचने से परहेज करें।

चीनी अधिकारी तिब्बत के अन्य मठों में भी इसी तरह के निष्कासन अभियान चला रहे हैं ताकि उनके अंदर अध्ययन करने वाले भिक्षुओं की संख्या को कम किया जा सके।

तिब्बती बौद्ध मठ और संस्थान न केवल तिब्बती बौद्ध धर्म, संस्कृति और पहचान के प्रतीक हैं, बल्कि इससे भी अधिक सदियों से यह वह स्थान है, जहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म का संरक्षण और समृद्धि हुई है। इन भिक्षुओं को मठों से बाहर निकालकर चीनी अधिकारियों ने जान-बूझकर उन्हें धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया और तिब्बती बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में बाधा डाली।

यह तिब्बती बौद्ध धर्म की साधना पर चीन के हमले से स्पष्ट संकेत है कि मठों को भविष्य में भिक्षुओं और भिक्षुणियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

• त्सोल्हो प्रांत में तिब्बती पार्टी के सदस्यों को घर में धार्मिक अनुष्ठान करने पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए

tibet.net, २४ नवंबर, २०२१

धर्मशाला। एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि चीनी सरकार ने हाल ही में आम्दो (चीनी : किंघई) प्रांत के त्सोल्हो (चीनी: हैनान) तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर (टीएपी) में सभी तिब्बती पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के धार्मिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।

इस प्रतिबंध के तहत पार्टी के सभी सदस्यों को घर पर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से बचना होगा। इस कारण उन्हें व्यक्तिगत धार्मिक पीठों और मंदिरों से अलग होने को मजबूर होना पड़ा।

हमारे सूत्र के अनुसार, आदेश का पालन नहीं करने पर सजा के रूप में सरकारी नौकरियों से निष्कासन और सरकारी लाभों और सब्सिडी से वंचित करने सहित मौलिक अधिकारों से वंचित होना पड़ सकता है।

सूत्र ने हमारे कार्यालय को बताया, 'इस तरह के उपायों ने क्षेत्र में तिब्बती पार्टी के सदस्यों को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने घरों में व्यक्तिगत बौद्ध मंदिरों और वेदियों को हटाने के लिए मजबूर किया है।'

वेदियां आमतौर पर तिब्बती घरों में देखी जाती हैं, जिनमें बुद्ध या अन्य आध्यात्मिक लामा या नेताओं की तस्वीरें होती हैं, जिन्हें वे अनुष्ठान और प्रसाद अर्पण करके अपना सर्वोच्च सम्मान देते हैं। यह तिब्बती बौद्ध धर्म की रिवाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और चीनी अधिकारियों को तिब्बती संस्कृति और पहचान की याद दिलाता है।

इसके अलावा, बौद्ध रीति-रिवाजों पर हमले के तौर पर मृतक परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के लिए अंतिम संस्कार पर और प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनके प्रार्थना सभाओं के आयोजन पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।

सूत्र ने कहा कि हालांकि, वर्तमान डिक्री केवल कुछ क्षेत्रों में लागू की जा रही है, लेकिन भविष्य में इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किए जाने की पूरी आशंका है।

२२ अप्रैल २०२१ को, चीनी सरकार ने 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए धर्म में विश्वास नहीं करने के लिए आचार संहिता (परीक्षण कार्यान्वयन के लिए)' लागू की है। इसमें 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' में पार्टी के सदस्यों के लिए धार्मिक रिवाजों पर प्रतिबंधों का व्यापक विवरण दिया गया।

'आचार संहिता' पार्टी के सदस्यों को साफ तौर पर सार्वजनिक और निजी जीवन- दोनों में किसी भी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने से मना करती है, जिसमें 'अपने परिवार के धार्मिक सदस्यों और रिश्तेदारों को भी घर पर वेदियां स्थापित करने, धार्मिक सामग्रियों को रखने, धार्मिक चित्रों और धार्मिक हस्तियों की तस्वीरें नहीं लटकाने की सलाह देना शामिल है।'

तिब्बत से सूचनाओं के बाहर भेजने पर चीनी सरकार के सख्त नियंत्रण और गंभीर प्रतिबंधों के कारण धार्मिक प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर अब तक सीमित जानकारी या कोई रिपोर्ट नहीं है। इस डिक्री के तहत त्सोल्हो टीएपी के पार्टी सदस्यों पर लगाए गए प्रतिबंध की रिपोर्ट इसके अस्तित्व में आने के बाद से व्यापक रूप से लागू किए जाने का संकेत देती है और वहीं की स्थितियों का चित्रण करती है।

'धर्म में विश्वास न करने के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए आचार संहिता' में पार्टी के सदस्यों को मार्क्सवाद, भौतिकवाद और नास्तिकता का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें पार्टी और उसके संविधान के प्रति पूरी तरह से वफादार रहने और अपने परिवार के सदस्यों को यह समझाने की भी आवश्यकता है कि धर्म पार्टी के संस्थापक सिद्धांतों और मिशन के विपरीत है।'

नौकरी दिए जाने के वादों के बावजूद तिब्बती विश्वविद्यालय के स्नातकों को काम नहीं मिल रहा है

• हान मूल के चीनियों से प्रतिस्पर्धा और मंदारिन भाषा में दक्षता की अनिवार्यता तिब्बतियों के लिए नौकरियों को दुर्लभ बनाती है।

rfa.org, सांग्याल कुंचोकी, २०२१.११.२२

तिब्बती सूत्रों का कहना है कि तिब्बती विश्वविद्यालय के स्नातकों को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में काम पाने में मुश्किलें आ रही हैं। शहर में एक चीनी सरकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों के अनुसार, हान चीनी नौकरियों के बाजार में बाढ़ आ गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार को काफी हद तक तिब्बतियों की पहुंच से बाहर रखा गया है।

१८ नवंबर को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नागरिकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी। सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसके बाद प्रतिक्रिया में आए २४६ में से लगभग एक तिहाई या ७० ईमेल का हवाला देते हुए बताया गया है कि तिब्बतियों के लिए बढ़ती अवसरों की कमी के कारण तिब्बती स्कूल छोड़ रहे हैं।

ल्हासा के तिब्बत विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने आरएफए से बात करते हुए कहा कि तिब्बती स्नातकों के लिए और अधिक नौकरियां पैदा करने के अधिकारियों के वादे हाल के वर्षों में पूरे नहीं हुए हैं।

आरएफए के सूत्र ने कहा, 'यह एक तथ्य है कि तिब्बती स्नातकों के लिए नौकरी खोजना बहुत कठिन रहा है। मैं भी नौकरी के बिना रह रहा हूं।'

उन्होंने कहा, 'सरकार ने २०१८ में वादा किया था कि वे विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, लेकिन अधिकांश पेशेवर नौकरियां अभी भी हान मूल के चीनी नागरिकों को दी जा रही हैं, इसलिए तिब्बती काम खोजने के

लिए संघर्ष कर रहे हैं।'

एक अन्य तिब्बती सूत्र ने आरएफए को भेजे एक ईमेल में कहा, 'पूर्व में विश्वविद्यालयों से स्नातक होने वाले तिब्बतियों के लिए शिक्षकों या मामूली सरकारी पदों पर नौकरी के कुछ अवसर उपलब्ध थे।'

उन्होंने कहा, 'हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान हान मूल के अनेक चीनी नागरिक विकास परियोजनाओं में काम करने के नाम पर तिब्बत चले आए हैं और यहां की नौकरियों पर कब्जा जमा लिया है, जिसके कारण तिब्बती स्नातकों ने नौकरी पाने के अपने सभी अवसरों को खो दिया है। अगर उन्हें नौकरी मिल भी जाती है तो उन्हें केवल अनुबंध के तहत काम पर रखा जाता है और दिहाड़ी के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है।'

भारत के धर्मशाला स्थित तिब्बत नीति संस्थान के एक शोधकर्ता कर्मा तेनज़िन ने आरएफए से बात करते हुए कहा कि जब तिब्बतियों को सरकारी पदों के लिए काम पर रखा जाता है, तब भी उन्हें अक्सर उनके प्रशिक्षण वाले क्षेत्रों से अलग के काम में या आमतौर पर स्कूलों में रखा जाता है।

तेनज़िन ने कहा, 'इसलिए यह रेखांकित करता है कि तिब्बती लोग अपनी शिक्षा के स्तर पर भी कैसे भेदभाव का सामना कर रहे हैं।'

सूत्रों ने पहले की रिपोर्टों में आरएफए को बताया कि तिब्बती नौकरी के अधिकांश आवेदक हाई-टेक फर्मों और निर्माताओं सहित निजी कंपनियों में काम पाने में असमर्थ रहे हैं। ये क्षेत्र नौकरी चाहने वालों के लिए पहली पसंद हैं और सिविल क्षेत्र के रोजगार में अच्छा खासा वेतन पैकेज देते हैं।

सूत्रों का कहना है कि नौकरियों के लिए होनेवाली परीक्षाओं में और रोजगार में मंदारिन चीनी भाषा में प्रवीणता की अनिवार्यता ने तिब्बती छात्रों को नुकसान पहुंचाया है। उधर, चीन तिब्बती क्षेत्रों में चीनी संस्कृति और भाषा के प्रभुत्व को बढ़ावा देना चाहता है।

आरएफए की तिब्बती सेवा के लिए तेनज़िन डिकी द्वारा अनुवादित। रिचर्ड फिने द्वारा अंग्रेजी में लिखित।

• 'फ्री तिब्बत: ए वायस फ्रॉम असम' ने गुवाहाटी में तिब्बती कार्यकर्ता के अभियान की मेजबानी की

tibet.net, १२ नवंबर, २०२१

तेनज़िन त्सुंडु और असम स्थित तिब्बत समर्थक समूह के साथ।

गुवाहाटी। तिब्बती लेखक और कार्यकर्ता तेनज़िन त्सुंडु अपने 'वॉकिंग द हिमालयज़' अभियान के तहत हिमालय की लंबी यात्रा पर हैं। तेनजिंग ने १७ अगस्त २०२१ को लद्दाख की राजधानी लेह से अपनी यात्रा शुरू की थी और पिछले ८७ दिनों में उन्होंने पांच में से चार भारतीय हिमालयी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का दौरा पूरा कर लिया है। वह गुरुवार ११ नवंबर २०२१ को पूर्वोत्तर भारत के द्वार के रूप में प्रसिद्ध असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। यहां पर तेनज़िन त्सुंडु का स्वागत असम स्थित एक तिब्बत समर्थक समूह 'फ्री तिब्बत: ए वॉयस फ्रॉम असम' के सदस्यों ने प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और लेखक श्री सौम्यदीप दत्ता के नेतृत्व में गर्मजोशी से किया। श्री दत्ता कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया के क्षेत्रीय संयोजक भी हैं।

बाद में शाम को 'फ्री तिब्बत: ए वॉयस फ्रॉम असम' की गुवाहाटी समन्वयक श्रीमती नोवनिता शर्मा एवं अन्य सदस्यों- सुश्री कंकना दास, श्री पंकज कुमार दत्ता, सुश्री बनानी दास और श्री बिकास बोरदोलोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसका शीर्षक था 'गुवाहाटी के गौहाटी प्रेस क्लब में 'तेनज़िन त्सुंडु से मिलिए' शीर्षक से एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया जहां तिब्बती कार्यकर्ता त्सुंडु ने अपने 'वॉकिंग द हिमालयाज' अभियान और इसके उद्देश्य, अपनी अब तक की यात्रा और अपनी आगे की यात्रा के बारे में मीडिया मित्रों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सक्रिय रूप से बातचीत की और मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया। प्रेस मीट में मीडिया बिरादरी और असम सिविल सोसाइटी के कुछ प्रमुख सदस्यों ने अच्छी तरह से भाग लिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों द्वारा इसकी कवरेज अच्छी तरह से की गई।

सदस्यों को 'एस्केप ऑफ दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत' नामक एक फिल्म भी दिखाई गई। यह फिल्म तिब्बत पर चीनी कब्जे और हिमालय की सीमाओं पर चीनी सैन्य दबाव का बोध कराती है। तेनज़िन ने बताया कि इस फिल्म का अभी तक अस्सी से अधिक बार प्रदर्शन हो चुका है। इसमें बयां की गई तिब्बत की कहानी और करुणा और अहिंसा में दलाई लामा के अडिग विश्वास के प्रदर्शन ने हमारे दर्शकों के मन के अंतस्थल तक को छुआ है। कई लद्दाखियों ने कहा कि यद्यपि परम पावन दलाई लामा उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, लगभग उनके भगवान की तरह। लेकिन साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि वे इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं कि वे दलाई लामा की वास्तविक कहानी को अब तक नहीं जानते थे। स्पीति और किन्नौर के लोगों ने कहा कि भारत में दलाई लामा की उपस्थिति ने उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को जीवित रखने में मदद की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने कहा कि दलाई लामा गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी द्वारा सिखाई गई करुणा और अहिंसा की महान विरासत को जारी रखे हुए हैं।

हिमालय की सैर या वाकिंग द हिमालयाज असल में तेनजिंग त्सुंडु की पांच हिमालयी भारतीय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा है। इसका उद्देश्य तिब्बत पर ७० वर्षों से चीनी कब्जे और भारत की ओर के हिमालयी क्षेत्रों पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जागरुकता पैदा करना रहा है। इस अभियान के तहत त्सुंडु ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अपना दौरा अभियान चलाया और भारत पर बढ़ते चीनी सुरक्षा खतरों

के प्रति लोगों को आगाह किया है। अब तक उन्होंने लद्दाख में लेह, कारगिल, ज़ांस्कर, नुब्रा, न्योमा और थिकसे का दौरा किया है; हिमाचल प्रदेश में लाहौल, स्पीति, किन्नौर; उत्तराखंड में दारचुला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा और हल्द्वानी; सिक्किम में लाचेन, नाथु-ला, नामची, रवंगला, गंगटोक, रुमटेक और वापस जाते समय कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, माने बंजांग, मिरिक, सोनाडा, कुसिआंग, ओडलबारी और सिलीगुड़ी के माध्यम से गांवों और कस्बों की यात्रा की। वह अब पांच हिमालयी राज्यों में से अंतिम अरुणाचल प्रदेश के रास्ते में हैं। वह तवांग, जंग, लुमला, जिममेथांग, दरांग, बोमाडिला की यात्रा करेंगे और राजधानी ईटानगर जाते समय जीरो, मेनचुखा, टुटिंग, तेजू और मियाओ होते हुए यात्रा करेंगे।

• कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया ने दिल्ली में अपने राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सह-संयोजकों और क्षेत्रीय संयोजकों की बैठक बुलाई

tibet.net, १५ नवंबर, २०२१

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया के सदस्य

नई दिल्ली। अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूहों (टीएसजी) के शीर्ष निकाय 'कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया (सीजीटीसी-आई)' ने रविवार, १४ नवंबर २०२१ को अपने राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सह-संयोजकों और क्षेत्रीय संयोजकों की एक बैठक बुलाई। बैठक में परम पावन दलाई लामा के नई दिल्ली स्थित ब्यूरो कार्यालय में प्रतिनिधि न्गोडुप डोंगचुंग, सीजीटीसी- आई के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर.के. खिरमे, राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार, सीजीटीसी-आई के क्षेत्रीय संयोजक श्री अरविंद निकोसे और आईटीसीओ कर्मचारी की उपस्थिति रही।

बैठक की शुरुआत समन्वयक जिग्मे त्सुल्ट्रिम के स्वागत भाषण के साथ हुई, जिन्होंने बैठक के एजेंडे पर सदस्यों और कोर ग्रुप के संबंधित सदस्यों से सीटीए के नए नेतृत्व की अपेक्षाओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला। बैठक की शुरुआत में उन सभी तिब्बती शहीदों और तिब्बत समर्थक समूहों के सदस्यों के लिए एक मिनट का मौन रखा गया, जिनका तिब्बत मुक्ति साधना की यात्रा में निधन हो गया।

सीजीटीसी-आई के राष्ट्रीय संयोजक सह बैठक के अध्यक्ष श्री आर.के. खिरमे ने अपने परिचयात्मक भाषण में भारत-चीन संबंधों के वर्तमान विकास, विशेष रूप से सीमा गतिरोध, जो तिब्बत के साथ-साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण है और तिब्बत मुद्दे को मजबूत करने के अवसर का उल्लेख किया। श्री ख्रिरमे ने कहा कि इसने कम्युनिस्ट चीन के दुष्ट विस्तारवादी मंसूबों के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा की है। श्री खिरमे ने आगे कहा कि चीन-तिब्बत वार्ता की बहाली महत्वपूर्ण है।

प्रतिनिधि श्री न्गोडुप डोंगचुंग ने अपने संबोधन में सदियों पुराने भारत-तिब्बत संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत और तिब्बत के ऐतिहासिक तथ्यों पर युवाओं को शिक्षित किया। उन्होंने सदस्यों के साथ तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति और तिब्बत में चीनी नेतृत्व के रवैये के बारे में लोगों को अवगत कराया। प्रतिनिधि ने तिब्बत के पर्यावरणीय मुद्दे पर भी बात की जिसका भारत के साथ-साथ अन्य एशियाई देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने सदस्यों से इसे तिब्बत की वकालत करने के अवसर के रूप में लेने और भारतीय नेताओं, संसद सदस्यों और अन्य संबंधित लोगों को इस मुद्दे पर जानकारी देने का आग्रह किया।

बैठक के एजेंडे के साथ, सदस्यों ने २७ फरवरी २०२१ को बेंगलुरु में आयोजित पिछली कोर ग्रुप बैठक द्वारा की गई कार्रवाई पर गहन चर्चा की। सदस्यों ने पिछली कोर ग्रुप बैठक के बाद से अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत कीं। सदस्यों ने भारत के आम लोगों के बीच तिब्बत पर जागरुकता पैदा करने और इस महत्वपूर्ण समय में तिब्बत के मुद्दे को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव सक्रिय रूप से साझा किए। इस संबंध में सदस्यों ने क्रमशः आगे की गतिविधियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। सदस्यगण तिब्बत के हित के लिए भारत में सभी तिब्बत समर्थक समूहों के साथ समन्वय में अधिक सक्रियता और सख्ती से काम करने के लिए भी सहमत हुए।

आईटीसीओ के उप समन्वयक तेनज़िन जॉर्डन ने सभी सदस्यों को कोविड-१९ स्थिति के बावजूद उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बैठक के एक दिन पहले सीजीटीसी-आई के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर.के. खिरमे, सीजीटीसी-आई के क्षेत्रीय संयोजक श्री सुंदरलाल सुमन और श्री पंकज गोयल की उपस्थिति में विभिन्न तिब्बत समर्थक समूहों के पदाधिकारियों के साथ आईटीसीओ में एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक भारत में विभिन्न तिब्बत समर्थक समूहों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए आयोजित की गई थी। सदस्य एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करने के लिए सहमत हुए और तिब्बत के मुद्दे को मजबूत करने के लिए योजनाएं और रणनीतियां निर्धारित कीं। संबंधित सदस्यों ने अपने विचारों और मतों का आदान-प्रदान किया, सुझाव दिए और तिब्बत के अच्छे मुद्दे के लिए संबंधित समूहों की सक्रिय भागीदारी की दिशा में निर्णय लिए।

• यूपी में बुद्ध पीजी कॉलेज द्वारा 'तिब्बत के लिए एक दिन' कार्यक्रम आयोजित किया गया

tibet.net, २४ नवंबर, २०२१

डॉ के एन मिश्रा।

धर्मशाला। उत्तर प्रदेश के जिस कुशीनगर में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण द्वारा संसार के इस नश्वर सत्य कि 'हर आदी का अंत होता है' के दर्शन को व्यावहारिक पक्ष को उजागर किया गया है, उसी कुशीनगर के बुद्ध पीजी कॉलेज में 'तिब्बत के लिए एक दिन' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कॉलेज में १२ विभाग हैं जिनमें लगभग ४००० छात्र अध्ययन करते हैं।

इस कार्यक्रम में बुद्ध पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. अमृतांशु शुक्ला; गणित विभाग के प्रोफेसर डॉ. सी.एस. सिंह; शिक्षक शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. निगम मौर्य; भूगोल विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कौस्तुभ नारायण मिश्रा, हिंदी विभाग के डॉ. गौरव तिवारी; वनस्पति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉ. वीणा कुमारी एवं अन्य विद्वान उपस्थित हुए।

डॉ. गौरव तिवारी ने तिब्बत के साथ भारत के संबंधों के मूल तत्वों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से भारत से उत्पन्न बौद्ध पारंपरिक शिक्षा को रेखांकित किया, जिसे तिब्बती विद्वानों और आचार्यों द्वारा संरक्षित किया गया था। ये वे साहित्य हैं जिन्हें भारतीय विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया और बाद में इनका तिब्बती से संस्कृत में पुनः अनुवाद किया।

डॉ. के.एन. मिश्रा ने चीन की आधिकारिक यात्राओं के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत के आधार पर चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा, उसकी निहित पूंजीवादी विचारधारा और इसकी विस्तारवादी नीति के बारे में अपनी जानकारी के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया। उन्होंने श्री इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों को याद किया, जिनमें तिब्बत मुद्दे के साथ-साथ कैलाश-मानसरोवर की आजादी का मुद्दा उठाया गया था।

डॉ. सी.एस. सिंह ने श्रोताओं से विशेष रूप से छात्रों से इस आयोजन से सीखी गई बातों को साझा करने और प्रत्येक व्यक्ति के मूल को समझने का आग्रह किया, जिसकी अलग-अलग कहानियां हैं, लेकिन उनका मूल एक ही सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ताने-बाने से जुड़ा हुआ है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होने के नाते डॉ. अमृतांशु शुक्ला ने इस कॉलेज से जुड़ी अपनी यादों को ताजा करने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया, जहां उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक अध्यापन किया और प्रशासन में सेवाएं दीं। उन्होंने न केवल भारत-तिब्बत संबंधों के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि इस ज्ञान और क्षमता को भी रेखांकित किया कि यह संबंध मानव जाति के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में योगदान कर सकता है।

भारत तिब्बत समन्वय कार्यालय के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, आईटीसीओ के लक्ष्य और उद्देश्य, सीटीए की नीति और कार्यप्रणाली और निर्वासन में तिब्बत की भविष्य की अपेक्षाओं और तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की भविष्य की अपेक्षाओं को 'तिब्बती जीवन शैली' नामक पीपीटी के माध्यम से रेखांकित किया।'

डॉ. निगम मौर्य ने कार्यक्रम के प्रत्येक वक्ता का परिचय दिया और छात्रों को इस आयोजन का सार्थक उपयोग करने की सलाह दी।

भारत-तिब्बत संवाद मंच, कुशीनगर के संयोजक डॉ. शुभलाल शाह और नामग्याल तिब्बती मठ, कुशीनगर के प्रभारी वें तेनक्योंग ने विशिष्ट आमंत्रितों को स्मारिका पुस्तकों के साथ तिब्बती स्कार्फ भेंट किए।

इस कार्यक्रम में तीन सौ से अधिक छात्रों और कुछ मीडिया प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

• समर्पित तिब्बत समर्थक स्वर्गीय मोहन सिंह के आवासीय एवं निर्वाचन क्षेत्र जिला देवरिया में एक दिन

tibet.net, २६ नवंबर, २०२१

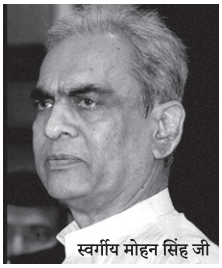
स्वर्गीय मोहन सिंह जी

देवरिया, यूपी। अगर आज अनुभवी राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोकप्रिय शख्सियतों में से एक ऐसी हस्ती का नाम लेने के लिए कहा जाए जो पिछले कई दशकों और खासकर ८० और ९० के दशक में तिब्बत के लिए अडिग होकर खड़ा रहा और तिब्बत के पक्ष में आवाज उठाते रहे हों, तो उस सूची में दिवंगत श्री मोहन सिंह का नाम न होने से वह सूची अधूरी रहेगी।

श्री मोहन सिंह समाजवादी नेता और एक राजनीतिज्ञ थे जो उत्तर प्रदेश के देवरिया से तीन बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने श्री जॉर्ज फर्नांडीस की अध्यक्षता में गठित 'ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंटरी फोरम फॉर तिब्बत (एपीआईपीएफटी)' के संयोजक के रूप में कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप ११९४ में नई दिल्ली में तिब्बत पर प्रथम विश्व सांसद सम्मेलन (डब्ल्यूपीसीटी) का सफल आयोजन हुआ।

२३ से २८ नवंबर २०२१ तक क्रमशः पडरौना के उदित नारायण पीजी कॉलेज और कुशीनगर के बुद्ध पीजी कॉलेज में आयोजित किए जा रहे 'ए डे फॉर तिब्बत' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए आईटीसीओ समन्वयक ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान दिवंगत मोहन सिंह के आवासीय और निर्वाचन क्षेत्र देवरिया जिले का दौरा करने का प्रयास किया गया। समन्वयक का यह प्रयास बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के महज संयोग था जो तिब्बत मुक्ति साधना के लिए मोहन सिंह द्वारा किए गए कार्यों के प्रति तिब्बतियों की कृतज्ञता को फिर से उजागर करना था।

श्री मोहन सिंह की पुत्री श्रीमती कनक लता सिंह देवरिया में नहीं, लखनऊ में रहती हैं। लेकिन वहां पर श्री विनोद जायसवाल ने न केवल श्री मोहन सिंह के मार्गदर्शन में काम करने के अपने अनुभव को साझा किया, बल्कि उनके आशीर्वाद और प्रेरणा को भी याद किया। उनको भरोसा है कि मोहन सिंह से मिली सहायता और मिले मार्गदर्शन उनके जीवन के बचे दिनों में उनको राह दिखा सकते हैं।

इसके अलावा, गांधी शांति प्रतिष्ठान और अवार्ड के पूर्व सचिव और वर्तमान में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार ने कुछ अन्य विशिष्ट सदस्यों से मिलने का सुझाव दिया, जिनके योगदान और विचारधाराओं ने तिब्बत के आत्मनिर्णय की यात्रा में और अधिक ऊर्जा प्रदान की हैं।

इस यात्रा के दौरान आईटीसीओ के समन्वयक न केवल स्वर्गीय श्री मोहन सिंह के आवास पर गए, बल्कि पूर्व एमएलसी श्री रामाशीष राय; प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक श्री हरदानंद जायसवाल; इलाहाबाद छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री अवनीश यादव और अन्य लोगों से भी मिले, जिन्होंने तिब्बत मुक्ति साधना के साथ जुड़ाव के अपने अनुभव साझा किए। इन लोगों ने तिब्बत मुद्दे को लेकर भारत और भारतीयों की अपेक्षाओं के बारे में अपने अनुभव बयां किए कि किस तरह से तिब्बतियों की पहचान को बचाए रखने के लिए तिब्बत मुद्दे के प्रति अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और करना चाहिए और चीनी कम्युनिस्ट विस्तारवादी नीति के खिलाफ तिब्बती की दुर्दशा को दर्शाते हुए आवाज को और अधिक बुलंद करना चाहिए।

• उत्तर प्रदेश के पडरौना में उदित नारायण पीजी कॉलेज ने 'ए डे फॉर तिब्बत' का आयोजन किया

tibet.net, २७ नवंबर, २०२१

'ए डे फॉर तिब्बत' के कार्यक्रम मे जुड़े छात्र और शिक्षक।

पडरौना, यूपी। भारत-तिब्बत संवाद मंच, कुशीनगर के संयोजक डॉ. शुभलाल शाह अपने चिकित्सकीय पेशे में मस्कुलोस्केलेटल बीमारी की देखभाल में अपनी विशेषज्ञता के अलावा तिब्बत के साथ भारत के संबंधों के ज्ञान को प्रदर्शित करने में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उनके प्रयास और उदित नारायण पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉ. ममता मणि त्रिपाठी की अनुमति से पडरौना शहर में 'ए डे फॉर तिब्बत' कार्यक्रम के तहत 'चीन-भारत संबंध में तिब्बत का कारक' शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पडरौना गोरखपुर से ९८ किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए उदित नारायण पीजी कॉलेज में भूगोल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. सी.बी. सिंह ने प्रो. समदोंग रिनपोछे और गेशे न्गवांग समतेन सहित तिब्बती विद्वानों के साथ अपने जुड़ाव को याद किया, जिन्होंने उन्हें भारतीय मूल्यों और उसके ज्ञान का अभ्यास करने के तिब्बती दृष्टिकोण की गहरी समझ के साथ एक अलग दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने छात्रों से इन विषयों पर फिर से विचार करने और यह समझने का आग्रह किया कि तिब्बत में भारत की शिक्षा का पारंपरिक ज्ञान कैसे सदियों से संरक्षित है।

उदित नारायण पीजी कॉलेज की प्राचार्या डॉ. ममता मणि त्रिपाठी ने कार्यक्रम के विषय और विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में तिब्बत के साथ भारत के संबंधों को जानने के अपने अनुभव पर विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से चीनी कम्युनिस्ट सरकार के नियंत्रण में तिब्बत की अतीत और वर्तमान स्थिति और भारत में पिछले छह दशकों से अधिक समय के दौरान निर्वासन में रह रहे तिब्बती प्रशासन के प्रयासों का संकेत दिया। उन्होंने न केवल इस कार्यक्रम को उस परिसर में आयोजित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जहां उन्हें हाल ही में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है, बल्कि उदित नारायण पीजी कॉलेज के शिक्षाविदों के इतिहास में अभूतपूर्व योगदान देनेवाले डॉ. सी.बी. सिंह को आमंत्रित करने पर भी खुद को सम्मानित महसूस किया।

भूगोल के प्रोफेसर डॉ. संजय सिंह ने न केवल पैनल के सदस्यों का परिचय कराया बल्कि अपनी पेशेवर विशेषज्ञता के साथ सत्र का आयोजन भी किया। उनके परिचय के साथ प्रत्येक वक्ता को पारंपरिक स्कार्फ और फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद ज्ञान की देवी सरस्वती माता के चरणों में दीप जलाए गए।

डॉ. शुभलाल शाह और सेफ हैंड्स एडवांस्ड लाइफ केयर इंस्टीट्यूट प्रा. लिमिटेड के निदेशक डॉ. गिरीश कुमार सिंह ने इस संबंध में क्रमशः तिब्बत के साथ भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक सीमाओं और पारिस्थितिक महत्व के बारे में अपने दृष्टिकोण साझा किए।

आईटीसीओ के समन्वयक ने अपने संबोधन में पडरौना में इस ऐतिहासिक यात्रा को संभव बनाने के लिए कॉलेज, इसके प्रशासनिक सदस्यों सहित मैडम प्रिंसिपल और उनके सहयोगियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने पीपीटी के साथ तिब्बत के इतिहास के श्वेत-श्याम से लेकर १९५० के दशक में विस्तारवादी कम्युनिस्ट चीन का शिकार हो जाने तक तिब्बती लोगों के रंगीन जीवन की कहानी प्रस्तुत की।

लगभग ५०० छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सत्र के अंत में प्रश्न किया जिसका उत्तर उन्हें दिया गया। इन छात्रों में विशेष रूप से भूगोल और राजनीतिक अध्ययन विभाग के छात्र और संकाय सदस्य शामिल रहे।

• भारत-तिब्बत समन्वय संघ ने 'तिब्बत और तिब्बती: वर्तमान और भविष्य' शीर्षक से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

tibet.net, २९ नवंबर, २०२१

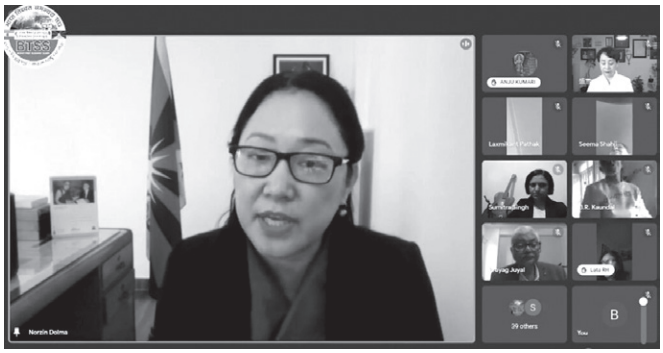

कलोन नोर्ज़िन डोलमा आभासी बैठक मे जुड़े।

धर्मशाला। भारत-तिब्बत समन्वय संघ (बीटीएसएस) ने प्रमुख शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, समाज शास्त्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और दुनिया भर के पत्रकारों को एक साथ लाने के उद्देश्य से २७ और २८ नवंबर २०२१ को 'तिब्बत और तिब्बती: वर्तमान और भविष्य' विषयक दो दिवसीय वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें उन लोगों को एक साथ लाने का विचार है जो तिब्बत के समर्थन में है और अपने शोध अनुभवों का आदान-प्रदान करने और साझा करने के लिए तैयार हैं। साथ ही जो ऐसा मंच प्रदान कर सकते हैं जो भारतीय और तिब्बती शैक्षणिक संस्थानों, स्वदेशी तिब्बती दवाओं, चिकित्सकीय कार्यों के साथ ही भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक सहजीवन की स्थापना में अंतःविषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला हो।

सम्मेलन के दौरान जिन विषयों पर व्यापक चर्चा की गई, वे थे तिब्बत में तिब्बतियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन, तिब्बत मुक्ति आंदोलन, तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत, विज्ञान और ध्यान के क्षेत्र में तिब्बती साहित्य का योगदान, तिब्बती दवाएं: दवा का एक वैकल्पिक तरीका और तिब्बती शिक्षा प्रणाली।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के मंत्री कालोन नोरज़िन डोल्मा उपस्थित थीं। वह भारत और तिब्बत की सामाजिक एकता, समानता और सुरक्षा पर कई मूल्यवान विचारों के साथ आगे आईं। भारत-तिब्बत संबंधों पर विशेष रूप से जोर देते हुए कालोन नोरज़िन ने कहा कि तिब्बत की बौद्ध संस्कृति तिब्बती पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह संस्कृति भारत से उत्पन्न हुई थी, जबकि बाद में यह तिब्बती राजनीति, इतिहास, कला और दवाओं का एक अभिन्न अंग बन गईं।

सीटीए की कालोन ने कहा, भारत जैसे महान राष्ट्र के प्रति परम पावन दलाई लामा के मन में जितना प्यार और विश्वास है उतना और किसी के मन में नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि परम पावन को दुनिया भर में लोगों द्वारा उनकी शांति और करुणा की भावना के लिए प्यार किया जाता है। परम पावन ने लगातार भारत को धार्मिक सद्भाव के लिए अनुकरणीय और भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विश्व समस्याओं का एक प्रासंगिक समाधान माना है।

संगोष्ठी के संरचनात्मक महत्व और इसकी भूमिका पर प्रो. मनोज दीक्षित (पूर्व कुलपति डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय) ने अपना वक्तव्य दिया। श्री ओपी तिवारी (पूर्व एयर वाइस मार्शल, भारत) ने तिब्बत की सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए और बताया कि तिब्बत भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। डॉ. एन. शिवा सुब्रमण्यम (पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, इसरो, भारत) ने तिब्बती विकास, सुधार और प्रचार पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। प्रो. पी.डी. जुयाल (संयोजक, आईसीटीटी-२०२१) ने सभी अतिथि वक्ताओं का स्वागत किया। प्रो. सुनील (एनआईटी, हमीरपुर) ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रथम सत्र का संचालन डॉ. सुमित्रा सिंह (एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा) द्वारा किया गया था। अंत में राष्ट्रगान के साथ सत्र का समापन हुआ।

पश्री प्रो. गेशे न्गवांग समतेन ने आईसीटीटी-२०२१ के विषय पर एक परिचयात्मक व्याख्यान दिया और भविष्य में इस तरह के और सम्मेलन आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया। प्रोफेसर (डॉ.) फुनस्टोग वांग्मो (अमेरिका) और डॉ. पेमा नामडोल (देहरादून) ने तिब्बती चिकित्सा के बारे में बताया। जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो में संयुक्त राष्ट्र की एडवोकेसी अधिकारी श्रीमती काल्डेन सोमो ने चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बात की। अंत में, तिब्बती स्वतंत्रता सेनानी श्री तेनज़िन त्सुंडू ने तिब्बत सीमा और इसके महत्व के बारे में जनता को जागरूक किया।

इस सम्मेलन के लिए दुनिया भर से कुल १२८ प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। प्रस्तुतीकरण के लिए १८ शोध पत्रों में से ८ शोधपत्रों का चयन किया गया। कुल ४ तकनीकी सत्र और २ पेपर प्रस्तुति सत्र आयोजित किए गए।

समापन सत्र का संचालन बीटीएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य श्रीमती ज्योति शर्मा ने किया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के माननीय पूर्व कुलपति हरिकेश सिंह इस सत्र के मुख्य अतिथि थे।

• तिब्बत पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, तिल का ताड़ बना सकता है चीन

newstraclive.com, ०२ नवंबर, २०२१

नई दिल्ली। भारत के मुख्य रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) बिपिन रावत ने रविवार को भारतीय सेना को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सेना को साल भर विवादित सीमाओं पर तैनात रहने की जरूरत है। रावत ने अपने संबोधन में चीन पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने सरदार पटेल का जिक्र करते हुए चीन को आइना दिखाया।

भारत के मुख्य रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) बिपिन रावत

बिपिन रावत के अनुसार, सरदार पटेल हमेशा तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखते थे। वे चीन और भारत के बीच सीमा संघर्ष को रोकने के लिए इसे एक बफर देश बनाना चाहते थे। रावत ने दावा किया कि सरदार ने पंडित नेहरू को लिखे पत्र में इसका जिक्र किया था। सरदार पटेल दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा एक स्वतंत्र तिब्बत का सपना देखा था। वे तिब्बत को एक बफर देश बनाना चाहते थे। इसका उल्लेख सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्र-व्यवहार में भी मिलता है।

अब यहां दो बातें जानना जरूरी है। पहला, यह बफर देश एक ऐसा देश है जो ऐसे दो देशों के बीच स्थित है, जहां लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। ऐसे में बफर देश के माध्यम से दूसरे देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की जाती है। दूसरी ओर, चीन ने हमेशा तिब्बत को अपना हिस्सा बताया है और जब बिपिन रावत सरदार पटेल के बयान के माध्यम से तिब्बत को स्वतंत्र बताते हैं, तो चीन के तिल को दोष देना तय है।

• निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी की पुस्तक का विमोचन किया और तिब्बत पर वार्ता में भाग लिया

tibet.net, ०९ नवंबर, २०२१

धर्मशाला। १७वीं निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा त्सेरिंग ने कल ०८ नवंबर को सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी की पुस्तक का विमोचन किया और तिब्बती प्रदर्शन कला संस्थान (टीपा) में भारत-तिब्बत सहयोग मंच द्वारा तिब्बत पर आयोजित वार्ता में भाग लिया।

निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर और सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी।

डिप्टी स्पीकर ने 'भारत-तिब्बत-चीन; २०२१ के नए परिप्रेक्ष्य में' के मुख्य भाषण में कहा कि चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मूल कारण है। इससे पहले स्वतंत्र तिब्बत इन दोनों देशों के बीच एक बफर राज्य के रूप में अवस्थित था। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि 'तिब्बत इस पूरे परिदृश्य का केंद्र है, तिब्बत की गंभीर स्थिति को सुलझाए बिना यह विवाद हल नहीं हो सकता है।'

तिब्बत की वर्तमान गंभीर स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, डिप्टी स्पीकर ने उल्लेख किया कि तिब्बत का २००० से अधिक वर्षों का लिखित इतिहास है और चीन के कब्जे से पहले यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था। उन्होंने कहा, 'चूंकि संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, दुनिया ने तिब्बत पर कब्जे को एकमात्र दर्शक की तरह देखा और चीन को तिब्बत पर कब्जा करने, आक्रमण करने और नष्ट करने दिया।' उन्होंने पूछा कि क्या हम तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मुक्त दुनिया में रहने वाले तिब्बती उनके प्रवक्ता हैं। उन्होंने तिब्बतियों से वैश्विक मंच पर चीन पर दबाव बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अधिक समर्थन हासिल करने के

लिए भी अपील की।

तिब्बत में १५५ तिब्बतियों के आत्मदाह पर सहानुभूति व्यक्त करते हुए डिप्टी स्पीकर ने बिना किसी बुनियादी मानवाधिकार के तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की विकट स्थिति का चित्रण किया और कहा, 'यह (आत्मदाह) चीन के प्रति किसी तरह की घृणा पाले बिना परम पावन दलाई लामा को वापस तिब्बत में देखने के लिए तरस रहे तिब्बतियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है और तिब्बत के पवित्र बौद्ध दृष्टिकोण से बलिदान का सर्वोच्च रूप है। वे हृदय में करुणा के साथ अपने शरीर को ज्वाला में अर्पित कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि चीनी सरकार ने मूल समस्या का समाधान करने की जगह परम पावन दलाई लामा पर दोष मढ़कर हमेशा एक आसान रास्ता निकाला है। इसके अलावा, चीनी सरकार वास्तविक मुद्दे को सुलझाए बिना अपनी अत्याचारी नीतियों को मजबूत करना जारी रखे हुए है और यहां तक कि परम पावन की तस्वीर रखने को भी आपराधिक कृत्य बना दिया है।

तिब्बत विश्व की प्रमुख नदियों का स्रोत है। इसके संदर्भ में डिप्टी स्पीकर ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से तिब्बती पठार के महत्व को समझाया और कहा कि चीन ने जल संसाधन को हथियार बनाकर दुनिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तिब्बत की नदियों पर सर्वाधिक संख्या में बांध बनाए हैं। उन्होंने जलवायु सम्मेलन कॉप-२६ में चीन की अनुपस्थिति और चीन में उत्पन्न होने वाले कोविड-१९ के प्रसार की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि चीन माउंट एवरेस्ट पर ५जी टावर लगा रहा है जबकि दुनिया कोविड-१९ की वजह से हो रही कठिनाइयों से जूझ रही है। परम पावन दलाई लामा पर निराधार आलोचनाओं का लेबल लगाने और साथ ही परम पावन के पुनर्जन्म प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और उनकी संस्था को हथियाने के लिए चीनी सरकार तरह तरह का पाखंड कर रही है। तिब्बत पर कब्जे के ६० वर्षों के बाद भी चीन तिब्बतियों का दिल जीतने में विफल रहा है, क्योंकि परम पावन हर तिब्बती के अखंड हृदय सम्राट हैं।

श्री संजय पराशर ने तिब्बतियों के साहस की सराहना की और चीन की विस्तारवादी नीति और चीन से उत्पन्न कोविड-१९ से हुई तबाही को उजागर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने बताया कि कैसे उन्हें तिब्बतियों और तिब्बत के मुद्दे से परिचित कराया गया और उन्होंने सराहना की कि कैसे तिब्बतियों ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तिब्बत से बहने वाली नदियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो वह पानी को लेकर होगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, विशिष्ट अतिथि श्री संजय पराशर, निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा त्सेरिंग, सांसद दावा त्सेरिंग, गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख और आम जनता उपस्थित रहे। डिप्टी स्पीकर डोल्मा त्सेरिंग ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी को ग्रीन तारा की एक थंगका पेंटिंग भेंट की, जबकि भारत-तिब्बत मैत्री संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री अजय सिंह मनकोटिया ने श्री संजय पराशर को बुद्ध की थंगका पेंटिंग भेंट की। डिप्टी स्पीकर को मेजर जनरल जी.डी. बख्शी द्वारा लिखित पुस्तकें भेंट की गईं और बदले में डिप्टी स्पीकर ने तिब्बती संसद द्वारा प्रकाशित पुस्तकें मेजर जनरल जी.डी. बख्शी और श्री संजय पराशर को भेंट कीं।

• 'कॉप-२६ टीम तिब्बत' वैश्विक जलवायु प्रणाली में तिब्बत की भूमिका को उजागर करने के लिए ग्लास्गो में

tibet.net, ४ नवंबर, २०२१

ग्लास्गो। संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 'कॉप-२६' में तिब्बत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तिब्बती पर्यावरणविदों की एक समर्थ टीम ग्लास्गो में है। वहां 'कॉप-२६ टीम तिब्बत' तिब्बती पठार के वैश्विक पारिस्थितिकीय महत्व को उजागर करने की कोशिश करेगी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित विश्व नेताओं से किसी भी वैश्विक जलवायु परिवर्तन चर्चा में तिब्बती पठार को केंद्रीय तत्व बनाने का आग्रह करेगी।

इस वर्ष, दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे अधिक संख्या में हिमनद वाले पठार की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से जोर देने के लिए तिब्बत नीति संस्थान के पर्यावरण डेस्क के अलावा चार अन्य तिब्बती संगठन एक टीम के रूप में ग्लास्गो में एकत्रित हुए हैं। टीम ने कॉप-२६ में विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बात की।

टीम में तिब्बत नीति संस्थान में रिसर्च फेलो डेचेन पाल्मो, पर्यावरण शोधकर्ता और अंतरराष्ट्रीय तिब्बत नेटवर्क में एशिया के क्षेत्रीय समन्वयक डॉ. लोबसांग यांग्त्सो, इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत के एडवोकेसी और अनुसंधान अधिकारी पाल्मो तेनज़िन, फ्री तिब्बत अभियान में छात्रों के लिए अभियान निदेशक पेमा डोमा और तिब्बत वॉच के वरिष्ठ शोधकर्ता तेनज़िन चोएक्यी शामिल हैं।

जलवायु संकट के 'टिकिंग बम' के बारे में बहुत चर्चा है और तिब्बत जलवायु संकट टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रखी हैं कि तिब्बत को इस चर्चा में शामिल किया जाए। ऐसे में सरकारें और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ग्रह के भविष्य की रक्षा के लिए इन योजनाओं को देखने के लिए विवश हो जाएंगे।

जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 'कॉप-२६' में तिब्बत का प्रतिनिधि

टीम तिब्बत वैश्विक जलवायु मुद्दे के रूप में तिब्बत के महत्व के बारे में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है और यहां तक कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन, पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर, हॉलीवुड अभिनेता एवं पर्यावरण प्रचारक लियोनार्डो डिकैप्रियो और जलवायु संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी के साथ बातचीत में तिब्बत मुद्दे को उठाने को तैयार है। उन्होंने प्रमुख हस्तियों और अन्य प्रतिनिधियों को 'तिब्बत पर कार्रवाई के लिए पांच सूत्रीय आह्वान (५ प्वाइंट कॉल टू एक्शन फॉर तिब्बत)' शीर्षक से एक लिफलेट या पत्रक भी सौंपे।

'तिब्बत के लिए ५-सूत्रीय आह्वान' पहली बार २०१५ में कॉप-२१ के लिए तैयार किया गया था। इसमें तिब्बती पठार की सुरक्षा और समझ के लिए पांच स्पष्ट मांगें हैं। 'तिब्बत के लिए ५-सूत्रीय आह्वान' में प्राथमिक मांग तिब्बती पठार के वैश्विक पारिस्थितिकीय महत्व के लिए मान्यता प्राप्त करना है और इसे वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में प्राथमिक विषय के रूप में शामिल कराने की आवश्यकता है।

अन्य जलवायु सम्मेलनों से कॉप-२६ में एक उल्लेखनीय अंतर यह है कि यहां चीन मंडप अनुपस्थित है। इसके अलावा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, इस तथ्य के बावजूद कि यह सभी सरकारों को स्थायी प्रतिबद्धता जताने के लिए एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है, घोषणा की है कि वह कॉप-२६ में भाग नहीं लेंगे।

अगले कुछ दिनों में टीम विशेष रूप से तिब्बत के निचले इलाके के देशों, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम (जलवायु मुद्दे पर संवेदनशील मंच) और द मार्शल आइलैंड्स जैसे छोटे द्वीप देशों के गठबंधन जैसे सहयोगी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी पैरवी के काम को आगे बढ़ाएगी।

टीम का उद्देश्य ग्लेशियोलॉजिस्ट (ग्लेशियर विशेषज्ञ) और पर्माफ्रॉस्ट विशेषज्ञों, जाने-माने कार्यकर्ताओं, उन गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी समूहों के साथ गठजोड़ करना है जो पानी के मुद्दों और गुलाम बना लिए गए देशों को लेकर काम कर रहे हैं। यह पैनल चर्चाओं का भी आयोजन करेगा और आने वाले दिनों में इंग्लैंड के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों में भाषण देगा।

• अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष रूप से चिंता वाले देशों की सूची में चीन को शामिल किया

tibet.net, १८ नवंबर, २०२१

धर्मशाला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की ओर से १७ नवंबर को जारी एक प्रेस बयान में बताया गया है कि विदेश मंत्री ने चीन के साथ-साथ बर्मा, इरिट्रिया, ईरान, डीपीआरके, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब जैसे देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित कर दिया है।

बयान में कहा, 'हर साल अमेरिकी विदेश मंत्री पर दुनिया भर की उन सरकारों और व्यवस्था से इतर के लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी होती है, जिनकी स्थिति धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की नीति के कारण अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत तय की जाती है।'

बयान में विदेश मंत्री ने कहा है, 'मैं बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, डीपीआरके, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित कर रहा हूं, जो 'धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, चल रहे और गंभीर उल्लंघन' के मामलों में शामिल हैं।'

उन्होंने कहा, 'मैं उन सरकारों के लिए विशेष निगरानी सूची में अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को भी रख रहा हूं, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन किया है या ऐसे उल्लंघनों को सहन किया है।'

विदेश मंत्री ब्लिंकन ने सभी और हर देश में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का भी वादा किया। उन्होंने नोट किया कि सरकारें दुनिया भर में बहुत से स्थानों पर अपनी मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए लोगों को परेशान करती हैं, गिरफ्तार करती हैं, धमकी देती हैं, जेल में डालती हैं और मार देती हैं। उन्होंने व्यक्त किया कि अमेरिकी प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति के धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इस मानव अधिकार के उल्लंघनकर्ताओं और दुर्व्यवहारियों का सामना करना और उनको रोकना शामिल है।

• लिथुआनिया ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने का आह्वान किया

tibet.net, १९ नवंबर, २०२१

लिथुआनिया ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने का आह्वान की

लंदन। लिथुआनियाई संसद (सेमास) में तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समर्थक समूह के अध्यक्ष एंड्रिअस नविकस और लिथुआनियाई सेमास के १७ सदस्यों के एक समूह ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने के लिए लिथुआनियाई सरकार, राजनेताओं और एथलीटों को दिए गए एक संयुक्त अपील-पत्र पर हस्ताक्षर किए। पत्र राष्ट्रीय टीवी समाचार और मीडिया में भी प्रकाशित हुआ।

आज अंग्रेजी और लिथुआनियाई दोनों भाषाओं में प्रकाशित संयुक्त पत्र में सदस्यों ने चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन और उग्यूर, तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के खिलाफ आक्रामकता और हांगकांग और ताइवान के प्रति आक्रामक व्यवहार के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। सदस्यों ने अपनी सभ्य आचरण प्रदर्शन में आनेवाली चिंताओं से भी अवगत कराया और उन आयोजनों में भाग लेने से परहेज करने का आग्रह किया, जहां उनका उपयोग सत्तावादी शासन द्वारा निर्देशित शो की कठपुतली के रूप में किया जाएगा।

उन्होंने लिथुआनियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से अपील करते हुए कहा, 'हम लिथुआनियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और लिथुआनिया में संचालित सभी खेल महासंघों के नेताओं से अपील करते हैं कि वे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहें, क्योंकि चैंपियनशिप ऐसे अधिनायकवादी व्यवस्था में नहीं हो सकते हैं, जहां मानवाधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता है और जहां शासन अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए खेलों को अपने पक्ष में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।'

• चीनी राष्ट्रपति की २०१६ यात्रा के दौरान चेक सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया: चेक अदालत का फैसला

tibet.net, १९ नवंबर, २०२१

जिनेवा। १८ नवंबर को चेक अदालत ने २८ मार्च २०१६ को प्राग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्राओं के विरोध में चेक गणराज्य के नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ अंतिम फैसला सुनाया। चेक अदालत ने लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में फैसला सुनाया और चेक पुलिस की कार्रवाई को 'गैरकानूनी' घोषित कर दिया।

प्राग में चीनी राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा के दौरान सैंकड़ों न्याय समर्थक और तिब्बत समर्थक चेक नागरिकों ने प्राग में रैली की थी, तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज लहराए थे और 'तिब्बत की स्वतंत्रता' सहित अनेक नारे लगाए थे। शी जिनपिंग की यात्रा का सार्वजनिक विरोध करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की घोषणा के बावजूद इस पर किसी तरह की आपत्ति जताए बिना चेक पुलिस ने 'यातायात नियमों' का हवाला देते हुए हरदज़नी स्क्वायर को बंद कर दिया। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों से चीनी नागरिक भिड़ गए। इसमें एक चीनी दंपति भी शामिल था, जिन्होंने एक चेक महिला

से तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज छीन लिया और उसे पास की वल्तावा नदी में फेंक दिया।

चेक अधिकारियों द्वारा कथित रूप से 'शर्मनाक' कार्रवाई के खिलाफ न्याय की तलाश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आयोजक-मार्टिन बर्सिक, कतेरीना बर्सिक जैक्स, टॉमस पिकोला, कतेरीना कुडलकोवा ने २९ मार्च २०१६ को मुकदमा दायर किया। मामले को शुरू में चेक निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया और बाद में इसे फिर से अपील के तहत नगरपालिका अदालत में दायर किया गया था।

अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए तिब्बत ब्यूरो जिनेवा के प्रतिनिधि छिमे रिग्जेन ने कहा, 'लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की यात्रा कभी आसान नहीं रही है। हालांकि, इतिहास ने साबित किया है कि सच्चाई हमेशा न्याय की ओर रहती है।' उन्होंने चेक अदालत के फैसले के लिए इतने वर्षों तक मजबूती से खड़े रहने के लिए सभी चेक गणराज्य के न्याय समर्थक, तिब्बत समर्थक और मानवाधिकार रक्षकों को धन्यवाद दिया। उनका मानना है कि चेक अदालत के फैसले लोकतांत्रिक देशों में बीजिंग के असंवैधानिक पद चिह्नों के बढ़ने के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में एक प्रेरणा के रूप में काम करेंगे।

इस केस के याचिकाकर्ता चेक सपोर्ट तिब्बत संगठन के अध्यक्ष मार्टिन बर्सिक ने कहा, 'अगर हमने मामले को कोर्ट में दायर नहीं किया होता तो यह हमारे लोकतंत्र की स्थिति को काफी कमजोर कर देता।' इसके अलावा, सह-याची केटीना बर्सिकोवा जैक्स ने कहा, 'मुझे खुशी है कि चेक गणराज्य एक उन्नत, पश्चिमी शैली के लोकतंत्र के रूप में कार्य करने का प्रयास करता है, न कि चीनी निरंकुशता के रूप में। २०१६ में चीनी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्राग में जो हुआ, वह शर्मनाक और गैरकानूनी था, जैसा कि अदालत ने फैसला दिया है। अदालत का फैसला उन सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो उस समय अपमानित महसूस कर रहे थे। यह फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य करेगा।

अदालत ने याचिकाकर्ता को मुकदमे में किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने का आदेश प्रतिवादी चेक सरकार को दिया।

• तिब्बती शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने गतिरोध से बहुत पहले एलएसी पर काम शुरू किया था

www.hindustantimes.com, २९ नवंबर २०२१

रेजाउल एच लस्कर

पिछले दो वर्षों से चीन की नीतियों को समझने में दुनिया की मदद करने के उद्देश्य से एक पुस्तिका तैयार करने पर काम कर रहे तिब्बती शोधकर्ताओं के एक समूह ने चीन की इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो अक्सर अस्पष्ट शब्दों में होती है और जाहिरा तौर पर जिसकी मनोनुकूल अलग-अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं।

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को एकतरफा तौर पर बदलने का प्रयास करने से एक साल पहले, चीनी अधिकारी अपने क्षेत्रीय दावों को पुष्ट करने और सीमा पार भारतीय पक्ष पर नजर रखने के लिए सीमावर्ती गांवों का उपयोग करने के उपाय कर रहे थे।

इस प्रवृत्ति को तिब्बती शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा उठाया गया था, जिन्होंने पिछले दो वर्षों से चीन की नीतियों को समझने में दुनिया की मदद करने के उद्देश्य से एक पुस्तिका तैयार करने पर काम किया था, जो अक्सर अस्पष्ट शब्दों में और अलग-अलग व्याख्याओं के लिए खुली होती हैं।

०२ दिसंबर को 'डिकोडिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी' शीर्षक से जारी होने वाली हैंडबुक के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे शोधकर्ताओं ने सीमावर्ती गांवों को सीमा के साथ प्रोजेक्ट फोर्स के साधन के रूप में उपयोग करने के चीनी पक्ष के ध्यान पर कई रिपोर्टें देखीं।

अगस्त २०१९ में तिब्बती में ऐसी ही एक रिपोर्ट चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और वेबसाइटों पर प्रसारित हुई जो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा से लगे शिगात्से प्रांत के गेरु गांव में सीमा पर गश्त और प्रचार गतिविधियों पर केंद्रित थी।

रिपोर्ट में 'सीमा रक्षा गांव' के रूप में वर्णित गेरु गांव में पार्टी सचिव- प्रथम के रूप में तैनात फुरबू सोनम के हवाले से कहा गया है, 'इन दिनों गेरु निवासियों में इस बात की मजबूत चेतना है कि यहां हर कोई एक जासूस है और हर घर एक जासूस घर है।'

सोनम ने कहा, 'यहां सेना के जवानों और स्थानीय निवासियों के बीच का रिश्ता मछली- पानी जितना गहरा है।' हर सोमवार को गेरु में तैनात स्थायी चीनी कार्यकर्ता चीनी ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए सीमा स्तंभ पर समारोह आयोजित करते हैं। सीमा सुरक्षा बलों की सहायता के लिए गांव के लगभग १०० लोग मोटरसाइकिल पर नियमित रूप से सीमा पर गश्त कर रहे हैं।

हैंडबुक के लिए सामग्री संग्रह करने वाले तिब्बती मानवाधिकार केंद्र की कार्यकारी निदेशक त्सेरिंग त्सोमो ने कहा कि परियोजना पर काम करने वाले पांच शोधकर्ताओं ने ऐसी और रिपोर्ट तैयार की हैं जो एलएसी के साथ चीन के इरादों की ओर इशारा करती हैं।

उन्होंने कहा, चीनी पक्ष न केवल तिब्बतियों को भर्ती करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि उन समुदायों की वफादारी सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहा है। 'इसके लिए बड़े पैमाने पर सोशल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। इसके तहत सीमावर्ती समुदायों को उद्यमों के लिए रोजगार और वित्त के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देना, और स्थायी निर्भरता और वफादारी बनाने के उद्देश्य से गांवों का निर्माण करना शामिल हैं।'

त्सोमो ने कहा, 'यह पुस्तिका चीनी पक्ष के इरादों का आकलन करने में लोगों की मदद करने का एक उपकरण है। कई देशों ने चीन को समझने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दिए हैं। हैंडबुक चीनी नारों और लोकप्रिय वाक्यांशों के अर्थों और निहितार्थों को उजागर करती है। उदाहरण के लिए, 'शी जिनपिंग थॉट' कई खंड लंबा है और विवेचना के लिए खुला है।

उदाहरण के लिए, तिब्बती शोधकर्ताओं का तर्क है कि अक्तूबर में लागू किए गए चीन के नए भूमि सीमा कानून भारत के लिए स्पष्ट चिंता का विषय है। शोधकर्ताओं ने कहा कि जनवरी से प्रभाव में आने वाला कानून चीन की भूमि सीमाओं के प्रतिभूतिकरण को और मजबूत करेगा।

चीन की १४ देशों के साथ भूमि सीमाएं लगती हैं, जबकि इसकी केवल भारत और भूटान के साथ सीमाएं अनसुलझी हैं।

कानून में सीमा के पास ड्रोन उड़ाने, अनिवार्य रूप से सैन्य निषिद्ध क्षेत्र रखने और

सुरक्षा एजेंसियों को अपराधी होने के संदेह पर भी किसी पर गोली चलाने के लिए अधिकृत करने जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूत दंडात्मक खंड हैं। शोधकर्ताओं का तर्क है कि कानून के अनुच्छेद-५३ का उद्देश्य पड़ोस के देशों में चीनी सैनिकों की उपस्थिति को मान्यता प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद- ११ का उद्देश्य तिब्बती खानाबदोशों को सीमावर्ती जिलों के गांवों में धकेलने और शिगात्से और ल्होका जैसे अन्य प्रमुख सीमावर्ती प्रिफेक्चर का निर्माण करना है, जहां चीन के प्रति वफादारी दिखाने की आवश्यकता है।

एक दूसरे लेख में बहुत ही अलग तरह के दीर्घकालिक प्रतिभूतिकरण की स्थापना की गई है, जिसके लिए सीमावर्ती प्रांतों के निवासियों को गहन सांस्कृतिक परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका उद्देश्य तिब्बतियों जैसे स्थानीय समुदायों को अपनी पहचान छोड़ने और सबसे पहले चीनी पहचान के साथ एकीकृत हो जाने के लिए प्रेरित करना है।

त्सोमो ने कहा कि चीनी नस्लीय नीति में 'इस तथ्य को त्याग दिया गया है कि चीन में ५६ राष्ट्रीयताएं शामिल हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके भीतर क्षेत्रीय नस्लीय स्वायत्तता की कानूनी गारंटी है।' अब इन तथ्यों को सांस्कृतिक आत्मसात करने के उद्देश्य में बदल दिया गया है।

(रेजाउल एच लस्कर हिंदुस्तान टाइम्स में विदेश मामलों के डेस्क के प्रमुख हैं)

ब्रुसेल्स, ३० नवंबर २०२१ : यूरोपीय संसद के तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप (टीआईजी) के साथ पूर्व तिब्बती राजनीतिक कैदी और तिब्बती फिल्म निर्माता श्री धोंडुप वांगचेन के साथ २०२२ मे होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार और तिब्बत पर हो रहे मानवाधिकार के हनन पर एक विशेष बैठक बुलाई। श्री धोंडुप वांगचेन २०२२ बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से पहले १५ यूरोपीयन देशों का दौरा करेंगे।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Jigmey Tsultrim
Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

जिगमे त्सुलट्रिम
समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः indiatibet7@gmail.com

November, 2021, Years: 42 Issue: 11 Regd No. : RNI 34636-79

कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया के बेठक मे राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सह-संयोजकों और क्षेत्रीय संयोजकों के साथ।

निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा त्सेरिंग ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी की पुस्तक का विमोचन किया और तिब्बत पर वार्ता में भाग लेते हुए।